an>

Title: Further combined discussion on the Budget (General) for 2014-15 and Demands for Excess Grants in respect of Budget (General) for 2011-12 (Discussion concluded).

HON. SPEAKER: The House will now take up Item No. 15 and 16 together.

Hon. Minister.

*__श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती)-__ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पहले आम बजट में उल्लिखित पूर्णतः जनहित को समर्पित प्रस्तावों की मैं प्रशंसा करता हूँ एवं समर्थन करता हूँ। भारत की जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया यह बजट निश्चित रूप से भारतीय जनमानस में खुशहाली लायेगा एवं देश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। संतुलित एवं हर वर्ग तथा हर समाज को ध्यान में रखकर प्रस्तुत इस आम बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती-बलरामपुर (उत्तर प्रदेश) में निम्न जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सम्पन्न कराने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव करते हुए इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान करके सरकार ने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है। सिंचाई में सुधार आने से भारत का किसान खुशहाल होगा। मैं इसके लिए भी भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलरामपुर-श्रावस्ती की भूमि बहुत उपजाऊ है, किंतु सिंचाई के साधनों के अभाव में किसान उपजाऊ जमीन से फसल का लाभ नहीं ले पाते हैं। अतः मैं सरकार के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के तहत बलरामपुर-श्रावस्ती जिले में सिंचाई के साधन मुहैया करवाए जाएं। राप्ती कैनाल परियोजना की धीमी गति के कारण परियोजना की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, अतः परियोजना तीव्र गति से पूरी करवायी जाये।

2. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के तहत श्रावस्ती में बौद्ध हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए उसे इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि छोटे और मझोले विमान आसानी से लैण्ड कर सकें और वहां से उड़ान भर सकें ताकि देश-विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और पर्यटन का विकास हो।

3. सोहेलवा वन प्रभाग श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में समेट कर भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्य जीव विहार का क्षेत्र है, जहां वन्य जीवों का प्राकृतवास है। अतः दुधवा और कतर्नियां की तरह सोहेलवा वन्य जीव विहार की नैसर्गिक छटा सैलानियों का स्वागत करने को तैयार है। बहते पहाड़ी नाले और शिवालिक पहाड़ियों का मनोरम दृश्य इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। बाघ, गुलदार, भालू, हिरन या फिर चीतल सभी जंगल में घूमते मिल जायेंगे। नेपाल की तलहटी से तराई के मैदानी इलाके तक फैला सोहेलवा वन प्रभाग को कुदरत से बेपनाह खूबसूरती की दौलत मिली है। सैलानियों की सुविधा के अनुरूप इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट तैयार करके सोहेलवा वन प्रभाग को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जाए।

4. बलरामपुर जिले की पहचान जर्जर और खस्ताहाल सड़कों से होती है, बलरामपुर मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी मुख्य मार्गों की हालत एक जैसी है। गोण्डा से बलरामपुर मार्ग की कुल दूरी 42 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में घण्टों लग जाते हैं। मार्ग की गिट्टियां जगह-जगह उखड़ी हैं। बलरामपुर उतरौला मार्ग सिद्धार्थनगर को जोड़ता है, इस सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है, इसे सी.आर.एफ. के अंतर्गत सुधारने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

5. बलरामपुर तुलसीपुर रोड से बेलहा मोड़ से इटवा सिद्धार्थनगर जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब है। अतः सी.आर.एफ. के अधीन चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत कर कार्य सुनिश्चित किया जाए। बौद्ध परिपथ को एन.एच. के अधीन तुलसीपुर से आगे सिद्धार्थनगर तक बढ़ाया जाए।

6. बहराईच भिनगा रोड 4 लेन का बनाया जा रहा है, भिनगा से चौधरीडीह तक 2 लेन का कार्य चल रहा है। चौधरीडीह से तुलसीपुर तक सी.आर.एफ. योजना में जोड़ दिया जाए।

7. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत श्रावस्ती एवं बलरामपुर को सम्मिलित किया जाये। ये दोनों जिलें अति पिछड़े हुए हैं। अतः इन जिलों में विद्युतीकरण से वंचित सभी गांवों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण सुनिश्चित करवाया जाये।

8. बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और नाना जी देशमुख की कर्मभूमि रही है। गोरखपुर और लखनऊ के बीच कोई मेडिकल कॉलेज न होने से मध्य पूर्वांचल के लोगों को काफी असुविधा होती है। अतः हमारी मांग है कि आदरणीय अटल जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बलरामपुर में स्थापित किया जाए।

श्रावस्ती की शिक्षा दर पूरे प्रदेश में न्यूनतम है। अतः मध्य पूर्वांचल के शैक्षिक विकास हेतु नानाजी के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना श्रावस्ती में की जाए।

__श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनू)-__ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट की भरपूर सराहना करती हूँ। भारत में पिछले दो वर्षों से आर्थिक विकास दर 5% से भी कम रही, दूसरी ओर विश्व के विकसित देशों में आये आर्थिक संकट से बाहर निकलने की जो गति है वह धीमी है। वहीं भारत की जनता के विभिन्नवर्ग इन परिस्थितियों से भारत को बाहर निकालने में असफल रहे। पूर्व सरकार के कारण एक नयी सरकार को नई उम्मीद के साथ चुना है। एक तरफ तो खजाना खाली और दूसरी तरफ आम जनता की उम्मीदें। इस कठिन परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक कुशाग्रता का परिचय दिया है, इसलिये वे निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं। यह बजट आगे भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा और दिशा रहेगी, कैसे सोयी अर्थव्यवस्था में गति आयेगी, रोज़गार निर्माण, गरीबी उन्मूलन, कमज़ोर वर्गों का उत्थान कैसे होगा। इन सबके लिये नीतियों का सूचक है। निश्चित रूप से यह बजट एक सकारात्मक शुरूआत है।

यह एन.डी.ए. सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगी, लेकिन इसके प्रति नीतियाँ बहुत ही प्रगतिशील और नयी हैं। यह घरेलू उद्योग और व्यवसाय की पूरक होंगी, न कि एक प्रतिद्वंदी की भूमिका में होगी। भारत में एक " नियो-मिडिल क्लास " का उदय हुआ है, जो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहती है और ये अभी हाल ही में गांवों से शहर को आये हैं। इसलिए एक सौ " स्मार्ट सिटी " को विकसित किया जायेगा। युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने हेतु बहुत-प्रतीक्षता (मल्टी स्किल्स) के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

इस बजट में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए काफी सशक्त योजनायें हैं। इस बार महिला सुरक्षा जो कि महिलाओं के लिए एक अहम् जरूरत है। " सार्वजनिक सड़क परिवहन सुरक्षा " योजना और बड़े शहरों में " क्राईसिस मैनेजमेंट सेंटर " खोलने की योजना प्रशंसनीय है। बालिकाओं के प्रति समाज और परिवार की उदासीनता को दूर करना इस सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए " बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं " जैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। महिलाओं को आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा में आने के लिए " जेंडर मेन स्ट्रीमिंग " कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, गाँवों की गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम " आजीविका " वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम, गाँवों के शत-प्रतिशत घंटों के विद्युतीकरण के लिए " दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " जैसे कार्यक्रम लागू किये जायेंगे। ये सारे कार्यक्रम नये रूप में, फलप्रद, उत्पादक और उपयोगी बनाये जायेंगे। गाँवों में सुरक्षित पेयजल और खासकर फ्लोराईड, आर्सेनिक जैसे प्रदूषकों से लड़ने के लिए सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। इसका मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ,क्योंकि मेरा जिला झुंझनू इस समस्या से काफी प्रभावित है।

भारत की कुल जी.डी.पी. का 1/6वाँ भाग कृषि से आता है और एन.डी.ए. सरकार इस बजट में कृषि के लिए अति महत्वाकांक्षी योजनायें लेकर आयी है। राजस्थान के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्वागत योग्य कदम है। दूसरी ओर हॉर्टीकल्चर विश्वविद्यालय का निर्माण भी स्वागत योग्य कदम है। कृषि को " ग्लोबल वार्मिंग " जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए " नेशनल एडपटेशन फंड " कृषि में 4थ की वृद्धि का लक्ष्य द्वितीय हरित क्रांति को प्रोटीन क्रांति की ओर मोड़ना, " भूमिहीन किसानों " के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित " सेल्फ हेल्प ग्रुप " का निर्माण, आठ लाख करोड़ रूपये, कृषि ऋण के लिए देना सरकार का कृषि क्षेत्र हेतु लिया गया सराहनीय कदम है।

जैसा कि सर्वविदित है कि लघु उद्योग का साधारणतः मालिकाना हक दलित, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के पास है और सरकार ने इनके उत्थान के लिए बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। इसमें उद्यमशीलता के विकास और नई कंपनी की शुरूआत के लिए 10,000 करोड़ का फंड मुहैया कराया है।

अब मैं राजस्थान को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद करती हूँ। " बन्धु कल्याण योजना " राज्य की जनजातियों के उत्थान के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है। राजस्थान के लिए 500 करोड़ रूपये सौर ऊर्जा के विकास के लिए, अजमेर को हेरिटेज सिटी बनाने हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

अंत में मैं अपने बजट संबंधी भाषण का समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल के वचनों से करना चाहती हूँ। वे भारत वर्ष के आदर्श पुरूष है और उनकी मूर्ति के निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपये इस बजट में भारत सरकार ने नियोजित किये हैं ताकि भारत की जनता भारत के उत्थान के लिए उनसे प्रोत्साहन ले। यह बजट उनके सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर है। इस बजट ने भारत के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है और जो उनके इस कथन को साकार करता है कः-

" मेरी एक इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भूखा न हो, जो अन्न के लिए ऑसू बहाता हुआ हो। "

***श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर)-** देश में तीन दशकों के बाद सशक्त जनादेश से बनी नरेन्द्र मोदी सरकार में वित मंत्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में पिछले तीन वर्षों से आर्थिक मंदी, मूल्य वृद्धि व अपूरणीय घाटे से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उत्व वृद्धि दर की ओर अग्रसर करने की एक सशक्त पहल की गयी है। इस बजट की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसानों, हस्तशिल्पियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, सैन्य बलों व अर्द्ध सैन्य बलों सहित देश के प्रत्येक छोटे व बड़े वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने का अधिकतम प्रयास किया गया है। बजट में राजस्व संसाधनों की कमी के उपरांत भी राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रख कर सरकार ने आर्थिक व वित्तीय अनुशासन पर भी अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया है। जबकि यू.पी.ए. के शासन में विगत तीन वर्षों में 2013-14, 2012-13 एवं 2011-12 में केन्द्र का राजकोषीय घाटा देश के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत व 5.7 प्रतिशत रहा है। इसलिये, यू.पी.ए. सरकार से विरासत में मिली ऐसी आर्थिक ह्रास एवं घाटे की अर्थव्यवस्था में मात्र डेढ़ माह में अचानक इससे अधिक कुछ कर लेना सहज नहीं था।

कर राहतः- सामान्य मध्यम वर्ग को कभी-कभी आयकर की दरों में कटौती की अपेक्षा विशेष रहती है। वर्तमान में हमारे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देश का कर राजस्व अतयंत न्यून होने एवं पिछले वर्ष की देयताओं को भी यू.पी.ए. सरकार द्वारा 2014-15 के लिए टाल देने से इस बार व्यय भार काफी था। तथापि, ऐसी परिस्थिति में भी आयकर सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर देने से छोटे आयकर दाताओं को पर्याप्त राहत मिली है। पब्लिक प्रोविडेन्ट फण्ड में भी कर मुक्त बचत की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर देने व अन्य भी कुछ और कर राहतों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष करों से होने वाली आय में सरकार को लगभग 22,200 करोड़ रूपये की राजस्व में कमी आयेगी। लेकिन इससे बचत, निवेश व आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में सहायता ही मिलेगी। प्रत्यक्ष करों में राहत की दृष्टि से सरकार द्वारा गृह ऋण पर चुकाये जाने वाले ब्याज की आयकर से कटौती हेतु सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर देने से जहाँ मध्यम वर्गीय लोगों को कर राहत मिलेगी, वहीं देश में आवास निर्माण व तत्संबंधी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को रोकने की सशक्त पहलः- विगत चार वर्षों से देश में उत्पादक उद्योगों की वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आ रही थी और वर्ष 2013-14 में उत्पादक उद्योगों की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गयी थी। उत्पादक उद्योगों में गिरावट का ऐसा दौर विगत 26 वर्षों में पहली बार आया है। ऐसे में बजट में औद्योगिक वृद्धि को पुनः गति देने के लिए जो अप्रत्यक्ष करो में राहत दी गयी है, उससे अवसंरचना क्षेत्र और उत्पादक उद्योगों के क्षेत्र में ही वृद्धि होगी। उत्पादक उद्योगों में भी लघु उद्योगों को दी गयी राहत से रोज़गार संवर्द्धक लघु उद्योग विशेष लाभांवित होंगे। किसी भी वर्ष में उत्पादन उद्योगों में नये संयंत्र व मशीनरी में 25 करोड़ रूपये का निवेश करने वाली इकाइयों को 15 प्रतिशत की दर में निवेश भत्ता मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगा। कई अन्य उद्योग श्रेणियों के लिए भी नये निवेश पर आयकर छूट दी गयी है। विद्युत उत्पादन, सप्रेषण और वितरण के क्षेत्र में दस वर्षीय कर अवकाश आगामी 31.03.2017 तक प्रदान करने के प्रस्ताव से देश ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ेगा। कुछ मामलों में घरेलू उत्पादन संवर्द्धन के लिए आदायों में जो सीमा शुल्क छूटें दी गयी हैं, उससे भी देश में कुछ और उद्योगों का विकास होने की अपेक्षा की जा सकती है। विगत वर्ष में चालू खाता घाटा चाहे सकल घरेलू उत्पाद के 2012-13 के 4.7 प्रतिशत के स्तर के दर से घटकर 1.7 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। तथापि, सीमा शुल्क में कटौती में सावधानी की आवश्यकता है, वह सावधानी इस बजट में रखी गयी है। अनेक अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि पिछले दिनों काले धन को निर्यात आय के रूप में वापस लाने से चालू खात घाटा में यह कमी आयी है।

कृषि सम्बंधी प्रमुख प्रावधानः- किसानों को कृषि कार्यों के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना एक प्रमुख समस्या रहती है। ऐसे में वर्ष 2014-15 में कृषि क्षेत्र के लिए 8 लाख करोड़ रूपये का कृषि क्षेत्र ऋण का लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। सस्ता बैंक ऋण सुलभ होने से किसान सूदखोरों के चंगुल से मुक्त होगा। ये ऋण उनको 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध होगा। उसमें भी समय पर पुनर्भुगतान करने पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन या छूट मिलेगी। कृषि के लिए 7 प्रतिशत पर ऋण और उसे समय पर लौटाने की दशा में उसमें 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन किसानों को वित्तीय राहत देगा। किसानों के अतिरिक्त, भूमिहीन किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे किसानों के 5 लाख संयुक्त कृषि समूहों को नाबार्ड के माध्यम से धन की व्यवस्था एक अच्छी पहल है।

कृषि में घटते निवेश पर नियंत्रण की दृष्टि से और उस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ रूपये की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में " दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि " स्थापित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे बैंक किसानों को स्थायी विकास हेतु दीर्घावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। देश में ऋणग्रस्तता के कारण बड़ी संख्या में किसानों ने विगत वर्षों में आत्महत्याएं की हैं, संस्थागत ऋण के अभाव में ऊँची ब्याज दरों पर गैर सरकारी स्रोतों से लिये अल्पावधि ऋणों के कारण ही ऐसा हुआ है। इस दृष्टि से " अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित निधि " के अंतर्गत 50,000 करोड़ के आबंटन से किसानों को उचित ब्याज दर पर समुचित अल्पावधि ऋण मिल सकेंगे। किसानों के तकनीकी ज्ञान में संवृद्धि और उन्हें आधुनिकतम तकनीकों आदि की समुचित जानकारी प्रदान करने और साथ ही जैविक कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान करने के लिए किसानी टी.वी. के नाम से 100 करोड़ रूपये के कृषि चैनल की स्थापना भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

कृषि उपजों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण उनकी उपज का उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से कृषि उपज के मूल्यों में अस्थिरता दूर करने के लिए 5 सौ करोड़ रूपये की मूल्य स्थिरिकरण निधि की स्थापना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलना संभव हो सकेगा। देश में देशी नस्ल का पशुधन आज विलोपन की ओर बढ़ रहा है। ऐसी दशा में बजट में देशी नस्ल के पशुधन के विकास के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि एक अच्छी पहल है। इसे देखते हुए लगता है कि सरकार इस दिशा में एक बड़ी पहल करने का मानस रखती है।

सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयासः- विगत 3 वर्षों से संसाधनों के अभाव से जूझती अर्थव्यवस्था की विरासत प्राप्त होने पर भी केन्द्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए संसाधनों के आबंटन व राहत के पर्याप्त प्रावधान इस बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत 50,548 करोड़ रूपये व जनजाति योजना के अंतर्गत 32,387 करोड़ रूपये का प्रावधान के साथ ही अनुसूचित जाति के उद्यमिता संवर्द्धन हेतु 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान और वनबन्धु कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये के अतिरिक्त आबंटन से एक सशक्त व नवीन पहल की गयी है। इसी क्रम में गांवों के शहरीकरण के लिए व वहाँ नगरीय स्तर की नागरिक आधारित रचनाएँ सुलभ कराने के लिए " श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरीकरण मिशन " के अधीन प्रस्तावित योजना गाँवों में निवास करने वाले वर्ग को समुचित सुविधाएँ प्रदान करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरो को 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुलभ करने के लिए " दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " के अंतर्गत घरो की आपूर्ति लाईनों के पृथककरण और बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान, ग्रामीण परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की दिशा में प्रभावी प्रयास सिद्ध होगा और उन्हें वर्ष भर 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुलभ हो सकेगी। इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान

के अंतर्गत 2019 तक प्रत्येक घर तक स्वच्छता (सेनिटेशन) की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के संवर्द्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से ग्रामीण गृह योजना के अधीन, ग्रामीण गृह विस्तार हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 8 हजार करोड़ का अतिरिक्त आबंटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 14 हज़ार 389 करोड़ रूपये के आबंटन, राष्ट्रीय ग्राम पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 36 सौ करोड़ के आबंटन से गाँवों में निवासरत परिवारों को भारी राहत मिलेगी।

देश में बड़ी संख्या में शिक्षित व अशिक्षित बेरोज़गार हैं, वही दूसरी और कौशल के अभाव में अनेक कार्यों के लिए हस्त-शिल्पी व कारीगर नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से देश की जनसंख्या के बड़े भाग को रोज़गार में नियोजन योग्य बनाने के लिए " दक्ष भारत " के नाम से विभिन्न प्रकार के हस्त-शिल्पों यथा वैल्डिंग, सुथारी, जुता मरम्मत, भवन निर्माण कारीगर या राज मिस्त्री, लोहारी, बुनकर आदि का कौशल विकसित करने का जो राष्ट्रीय बहुदक्ष कार्यक्रम (मल्टी स्किल प्रोग्राम) प्रस्तावित किया है, वह देश में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। बुनकरों के लिए 50 करोड़ रूपये के प्रावधान, ग्रामीण स्वरोज़गार के लिए " आजीविका " के नाम से महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमिता के विकास हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान नीरांचल के नाम से " जल संग्रहण परियोजना " के लिए 2,142 करोड़ रूपए का प्रावधान जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में आम व्यक्ति में स्वावलम्बन विकसित कर अच्छा आर्थिक परिवर्तन आएगा।

मोदी सरकार के इस पहले बजट में महिला सुरक्षा पर 150 करोड़ रूपये का प्रावधान, पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट पर प्रायोगिक परीक्षण परियोजना पर 50 करोड़ का प्रावधान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं जैसे कार्यों पर 100 करोड़ रूपये का प्रावधान, मातृशक्ति के प्रति परिवेदन क्षमता का परिचायक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों की रचना के प्रस्ताव और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में मुद्रण और ब्रेल लिपि वाले करेंसी जैसे छोटे-छोटे कर्मों पर केन्द्रित योजनाएँ, विभिन्न वर्गों को उचित राहत देने वाली सिद्ध होगी। लोक कल्याण की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान पर 28,600 करोड़ रूपये और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर 4,966 करोड़ रूपये के प्रावधान विद्यालयीन शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगे, वहीं 500 करोड़ रूपए के प्रस्ताव वाला पं. मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षक गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5 आई.आई.टी. और 5 आई.आई.एम. की स्थापना से ज्ञान आधारित क्षेत्रों में रोज़गार के लिए जन संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। नये अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थानों के प्रस्ताव और 12 नये मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देंगे। नदी जोड़ा परियोजना पर प्रतिवेदन के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान अंततः देश में नदी जोड़ने की क्रांतिकारी योजना के लिए नींव का पत्थर सिद्ध होगा।

रक्षाः वांछित प्राथमिकताः - देश के चारों ओर बाह्य सुरक्षा संकटों को देखते हुए रक्षा पर 2 लाख 30 हज़ार करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ पिछले बजट की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि स्वागतयोग्य है। सैनिकों के लिए एक रेंक, एक पेंशन योजना जेसे प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान और रक्षा आधुनिकीकरण के लिए 5 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सुरक्षा के प्रति सरकार की उच्च संवेदनशीलता का परिचायक है।

पर्यटन व संस्कृतः- पर्यटन पर 500 करोड़ रूपये, तीर्थ स्थानों के विकास पर 100 करोड़, विरासत नगरी यथा मथुरा, अमृतसर, गया, कांतीपुरम आदि के लिए 200 करोड़ का प्रावधान, पुरातात्विक महत्व के स्थानों के विकास पर 100 करोड़ रूपए का प्रावधान जैसे प्रस्ताव संस्कृति एवं पर्यटन के संवर्द्धन को बढ़ावा देने वाले हैं। पावन नदियों के संरक्षण, इनकी शुद्धता, घाटों के विकास, "नमामि गंगे "के अंतर्गत एकीकृत गंगा संरक्षण पर 2037 करोड़ का प्रावधान सभी धर्मप्राण राष्ट्रवासियों के लिए प्रसन्नतादायक है। घाटों के विकास के लिए अमरनाथ, केदारनाथ विभिन्न स्थानों पर 100 करोड़ रूपए का प्रावधान भी हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान की अच्छी पहल है। पूर्वोत्तर विकास हेतु मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, 12 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, कृषि अनुसंधान, नदी जोड़ो परियोजना पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान पूर्वोत्तर के लिए जैविक कृषि संवर्द्धन प्रस्ताव, रेल संयोजन, अरूण प्रभा जैसे टी.वी. चैनल का प्रावधान सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देंगे।

बजट में नये बंदरगाहों, विमान पत्तनों एवं राजमार्गों के विकास और आंतरिक नौवहन आदि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर समुचित निवेश के प्रावधानों से भी निवेश व रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

***योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर)-** सन् 2014-15 का आम बजट जिसे माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा 10 जुलाई,2014 को इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर गौर किया जाए तो देश के अंदर आम बजट प्रस्तुत करना किसी चुनौती से कम नहीं था और खास तौर पर जब खराब मानसून और ईराक संकट ने इस चुनौती को बढ़ा दिया हो।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सामने जहां महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती है, तो वहीं वित्तीय घाटा कम करना और विकास दर को तेज करने की एक भारी चुनौती भी है। उस सबके बावजूद समाज के सभी तबकों का ध्यान रखते हुए एक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को बधाई देता हूँ। यह बजट न केवल वित्तीय घाटे को 4.1 प्रतिशत से कम करके 3.5 प्रतिशत तक लाने में सफल होगा,अपितु महंगाई पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में सफल होगा। आर्थिक सुधारों और सामाजिक सरोकारों को एक साथ चला पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन दोनों मोर्चों पर अपना अचूक निशाना साधने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, हमें विश्वास है कि सरकार इसमें संतुलन बनाने में सफल रहेगी। इस सरकार को ऐसे समय में देश की बागडोर मिली है, जब देश की आर्थिक स्थिति डावांडोल है। सकल घरेलू उत्पाद पिछले 2-3 वर्षों में 5 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है और इसी में खराब मानसून और ईराक संकट " कोढ़ में खाज " का काम कर पा रहा है। सीमित विकल्पों में सावधानीपूर्वक महंगाई पर लगाम लगाते हुए वित्तीय घाटा कम करना अत्यंत आवश्यक है। बजट में

इस प्रकार की सकारात्मक सोच स्पष्ट परिलक्षित होती है। अब तक नई सरकार ने जो कार्य संस्कृति विकसित की है, वह इसका उदाहरण है।

कर प्रक्रिया में सरलीकरण से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उद्योग एवं व्यापार में निवेश बढ़ेगा। इससे भी विकास में तेजी आएगी। बजट भाषण में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने से भी उद्योग और व्यापार को जहां एक नई दिशा मिलेगी, वहीं निर्यात को भी गति मिलेगी। महंगाई से त्रस्त मध्यम आय वर्ग की परेशानी को ध्यान में रखकर आयकर में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करना, धारा 80 सी के तहत बीमा प्रीमियम, पी.पी.एफ. तथा पी.एफ के लिए 1 लाख से छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख करना, आवास ऋण में ब्याज की सीमा 1.5 लाख से 2 लाख करना महंगाई से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। रोज़गार कार्यालयों को युवाओं के कैरियर केन्द्र के रूप में बदलने और उनके लिए विशेष अवसर विकास केन्द्रों की स्थापना करना युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूँकने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु निवेश बढ़ाने की बात कही गई है। सड़क, पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा, स्मार्ट सिटी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा उपलब्ध कराने, आवासी और सामाजिक क्षेत्र के विकास तथा वित्तीय क्षेत्र में बचत आदि तमाम ऐसे प्रावधान हैं, जो अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक होंगे।

" प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना " खेती की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के तमाम कार्यक्रम गांव से पलायन को रोकने में मददगार होंगे।

बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बीमा योजना की पुनर्वहाली, ई.पी. स्कीम से सभी अंशदाता सदस्यों से रू. 1000 के प्रतिमाह का न्यूनतम पेंशन की सुविधा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए घोषित कार्यक्रम, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मुद्रा में चिन्हित करना तथा 15 नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना तथा 10 मौजूदा ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण की घोषणा इस सरकार के सामाजिक सरोकार को प्रदर्शित करता है तथा बजट भाषण में " बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं " की घोषणा, सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार के महिला सुरक्षा और उत्थान के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।

सबके लिए स्वास्थ्य की घोषणा, देश के अंदर 4 नए आयुर्विज्ञान संस्थान जिसमें से एक पूर्वी उ.प्र. के लिए भी घोषित हुआ है, के लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि पूर्वी उ.प्र. के लिए घोषित आयुर्विज्ञान संस्थान को गोरखपुर में स्थापित किया जाए।

अध्यापकों के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण हेतु पं. मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्ट कार्यक्रम की घोषणा तथा देश में 5 नए आई.आई.टी. तथा 5 नए आई.आई.एम. की घोषणा स्वागतयोग्य है। मौजूदा समय में देश के अंदर 13 राज्यों में आई.आई.एम. हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, रायपुर तथा तमिलनाडु हैं तथा 15 राज्यों में आई.आई.टी. हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में दो कानुपर और वाराणसी, उत्तराखण्ड में रूड़की, भुवनेश्वर, चैन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन्दौर, गांधीनगर, जोधपुर, खड़गपुर, मण्डी, दिल्ली, मुम्बई, पटना, रोपड़ है। आई.आई.टी., आई.आई.एम. तथा एम्स जैसी संस्थाएँ अगर इसी प्रकार देश के अंदर खुलती रहीं तो आने वाले समय में विश्वस्तरीय संस्थानों की कमी नहीं रहेगी। इस सम्बंध में मेरा माननीय वित्त मंत्री से प्रस्ताव है कि पूर्वी उ.प्र. के गोरखपुर के लिए भी एक आई.आई.टी. और एक आई.आई.एम. स्वीकृत किया जाए।

लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन स्वागतयोग्य है। इस प्रकार का प्रावधान अन्य 10 लाख की आबादी वाले नगरों के लिए भी किया जाना चाहिए और मेट्रो की सुविधा आस-पास के कस्बों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में गोरखपुर महानगर को मेट्रो सुविधा से जोड़ने और उसे पिपराइच, भटहट, पीपीगंज, सहजनवां, बासगांव, कौड़ीराम, चौरी-चौरा तक विस्तार दिया जाए।

कृषि इस देश में सदैव से स्वावलम्बन का एक आधार रहा है। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र की हुई उपेक्षा के कारण किसान बदहाल हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि का योगदान लगातार कम हुआ है। सन् 1950 में यह योगदान 50 प्रतिशत से अधिक था, आज यह मात्र 14 प्रतिशत रह गया है। कृषि के लिए पहली बार सरकार की संवेदना जागती हुई दिखाई दी। प्रत्येक किसान के लिए मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा तथा 100 चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, असम और झारखण्ड में 2 उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, 2 कृषि विश्वविद्यालय और 2 बागवानी विश्वविद्यालय की घोषणा, स्वदेशी पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए योजना की घोषणा करना तथा कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रूपये की घोषणा स्वागतयोग्य है। पूर्वी उ.प्र. के गोरखपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

देश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना, जिससे देश के अंदर औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा तथा रोज़गार के बेहतर सृजन भी होंगे और देश की विकास दर भी बढ़ेगी। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जल मार्ग का विकास, गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए " नमामि गंगे " के लिए धन का आबंटन, नदियों को जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए धन का आबंटन स्वागतयोग्य है। कृषि के बाद देश में रोज़गार सृजन के लिए वस्त्र उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा देश के अंदर 6 स्थानों पर हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने के लिए धन का आबंटन स्वागतयोग्य है। " एक रैंक-एक पेंशन " को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए धन आबंटन, पूंसेस पार्क के लिए 100 करोड़ रूपये, युद्ध स्मारक के लिए भी 100 करोड़ रूपये का प्रावधान करना देश के सैनिकों का सम्मान है। पुलिस का आधुनिकीकरण आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास करने के लिए धन का आबंटन करना देश के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की विजय है तथा हिमालय जो हमारे उत्तरी सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ जैव विविधता का केन्द्र भी है, के लिए राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन केन्द्र की स्थापना स्वागतयोग्य है।

यूरिया और खाद्य सब्सिडी को न हटाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना तथा एक यूरिया नीति की घोषणा स्वागतयोग्य है। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की बंद गोरखपुर समेत सभी उर्वरक संयंत्रों का पुनरूद्धार किया जाए। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट का समर्थन करता हूँ।

*__श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) :__ मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा 12 जुलाई को लोक सभा में आम बजट पेश किया गया यह बजट देश की आम जनता की उम्मीदों के विपरीत रहा । इस बजट में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेश भी उपेक्षा के शिकार रहे। इस बजट में कोई भी स्थायी योजना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लायी गयी जैसा कि सभापति महोदय जो आपको अवगत होगा कि फिरोजाबाद जिला प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है । यहां कांच एवं चूड़ी का प्रमुख उद्योग है । और इसी कारण इसे इतिहास में सुहागनगरी के नाम से जाना जाता है । माननीय वित्त मंत्री साहब जी ने अपने बजट में कांच उद्योग की पूर्णतया उपेक्षा की गई है ।

जैसाकि चुनाव में भाजपा द्वारा अनेक लोक-लुभावन नारे दिये गये थे, लेकिन यह सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह केवल वादे तक ही सीमित रह गयी माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय ऐसी किसी भी स्थायी योजना की बात नहीं कि जिसे जनता की उम्मीदें थी । देश की जनता नयी सरकार को नया सवेरा के रूप में देख रही थी, लेकिन परिणाम इसके ठीक विपरीत रहा ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में किसानों की समस्या के साथ-साथ, शिक्षा, उद्योग आदि की भी उपेक्षा की गयी । बजट 2014-15 में आम आदमी के ऊपर बोझ साबित हो रहा है । क्योंकि इस बजट में किसी भी दीर्घकालीन योजना की बात माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा नहीं की गयी है ।

इस आम बजट में माननीय मंत्री जी द्वारा सामाजिक ढांचे के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों की भी उपेक्षा की गयी, इस सरकार ने केवल पूंजीपतियों के फायदे को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस बजट में क्या ऐसा कोइ प्रावधान किया है जिससे जनता का भी भला हो सके ।

*__श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट)-__ सर्वप्रथम मैं भारत के वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत की जनता के हितों की रक्षा करने वाला दूरदर्शी एवं विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। वित्तमंत्री के सम्मुख अनेक चुनौतियां थीं। देश की विकास दर 5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक पहुँच चुकी थी, जबकि मुद्रास्फीति की दर द्विअंकी बन चुकी थी। इसके अलावा बेरोज़गारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, कमज़ोर आधारभूत संरचना एवं गरीबी जैसे प्रश्नों ने भारत के अर्थव्यवस्था को अत्यंत विकट स्थिति में धकेल दिया था। ऐसे समय में वित्तमंत्री ने समग्रतापूर्ण दृष्टि वाला बजट प्रस्तुत करके भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने की पहल की है। वित्तमंत्री ने देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति से जुड़े हुए विषयों का समावेश अपने बजट में किया है और बढ़ रही महंगाई से देश के प्रत्येक नागरिक को सहूलियत देने का प्रयास किया है। सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को प्राधान्य दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की घोषणा की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और मार्ग निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14,389 करोड़ रूपये की रकम का आवंटन किया गया है। महिलाओं के स्व-सहाय समूहों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा होने से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की है। इस प्रकार भारत के शहर अधिक स्वच्छ, सहूलियत पूर्ण एवं रहने योग्य बनेंगे। इसके अलावा सरकार ने भारत के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार का यह निर्णय प्रशंसनीय है। सरकार ने निर्णय लिया है कि 2019 तक देश के प्रत्येक घर को मूलभूत सेनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 12 नये मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाकर केवल 6 महीनों में कुपोषण से लड़ने की सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रूपये एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4166 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। ऐसा होने से भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होगा। इस बजट में वित्त मंत्री ने कृषि, स्वास्थ सुरक्षा, उद्योग, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि अनेक क्षेत्रों में अपनी दीर्घादृष्टि द्वारा विकास की संभावनाओं का आकलन करके उसे वास्तविक स्वरूप प्रदत्त करने की दिशा में अनेक प्रावधान किये हैं। वित्त मंत्री द्वारा किये गये प्रावधानों का सम्मान करने के साथ-साथ मैं यहाँ अपने कुछ नम्र सुझाव देना चाहता हूं।

इस वर्ष कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर ऐसा हुआ तो खाद्यान्न के उत्पादन में भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि देश में खाद्यान्न की उपलब्धता पर कोई विपरीत असर न पहुंचे एवं खाद्यान्न के दामों में वृद्धि न हो।

सरकार ने एन.एच.आर.एम. के तहत एक सर्वव्यापक बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। जब भी इस प्रकार की योजना अस्तित्व में आए तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके तहत गरीबों को मुफ्त में दवाई एवं चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए।

एन.डी.ए. की सरकार ने देशभर में पक्की सड़कें बनवाने के लिए निर्णय लिया है। मेरी यह गुज़ारिश है कि देश की सभी बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए, जिससे की समग्र देश में परिवहन सरल और सुलभ बन सके।

अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो राजकोट ज़िला उद्योग क्षेत्र में संपूर्ण भारत में अग्रसर है। राजकोट, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है। धार्मिक एवं अध्यात्मिक क्षेत्रों में सौराष्ट्र का स्थान प्रमुख है। यही कारण है कि सौराष्ट्र को वायु मार्ग से दिल्ली से जोड़ा जाए। सौराष्ट्र के 2 करोड़ और राजकोट के 25 लाख लोगों की ओर से मैं आपसे विनती करता हूँ कि राज़कोट और दिल्ली के बीच में एयर इंडिया की विमान सेवा तुरंत शुरू की जाए।

वर्ष 2012-13 के दौरान किये गये मूंगफली और कपास के दावों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2012 में 48262 हैक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली बोयी गयी थी। इस संबंध में बीमा एजेंसियों ने प्रीमियम भी वसूल कर लिया था, किंतु अब तक फाईनल सेटलमेंट हो नहीं पाया है। यह बात अत्यंत गंभीर है, क्योंकि किसान अत्यंत विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इन किसानों को तुरंत ही बीमे की रकम चुकायी जाए।

सरकार ने बजट में देश के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति का ध्यान रखा है। लोगों ने इस बजट को प्रेमपूर्वक अपनाया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी और देश को विकास के उच्च क्षितिज तक ले जाएगी।

*__*__**श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)-** वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट भारत के चहुँमुखी विकास की आधारशिला है। भारत की जनता ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपना मत दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जनमानस ने पूर्ण बहुमत दिया है, जो पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सारे विश्लेषक सर्वे राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को नकारते हुए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। आज भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। देश का युवा परिवर्तन चाहता है। भारत का युवा विकास चाहता है, उसने विकास को वोट किया है। आज का युवा ग्लोबल विलेज की कल्पनाओं को साकार करना चाहता है। इस दिशा में यह बजट निर्णायक बजट है। यह बजट रोज़गार सृजन मजबूत,आधारभूत संरचना सुशासन की दिशा को आगे ले जाने वाला है।

भाजपा शासन का यह पहला बजट है। यह बजट पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित है। यह बजट चाणक्य के सिद्धांतों पर चलने वाला है, जो यह बताता है कि शासन को जहां सबकी चिंता करनी चाहिए, वहीं करो का संग्रह उस प्रकार से करना चाहिए जैसे सूर्य समुद्र से जितना पानी वाष्प के रूप में लेता, उसे वर्षा के रूप में धरती को वापस कर देता। इसी प्रकार शासन को भी जनता से कर संग्रह करना चाहिए। बिना अतिरिक्त बोझ दिये, यह बजट किसान,गरीब,भूमिहीन, मजदूर, अनुसूचित जाति,जनजाति, महिला, युवा, बुजुर्ग एवं ग्रामीण भारत के हितों को प्राथिमकता देनेवाला है। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत 2014-15 का यह बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित सबका साथ-साथ विश्वास नारे के प्रति प्रतिबद्धता का कार्यरूप है। यह बजट देश के कोने-कोने को विकास से जोड़ने वाला है। इस बजट से भारत उन ऊँचाईयों को हासिल कर सकता है, जिनका भारत सही में हकदार है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को विश्व में शक्ति केन्द्र बनाने की यात्रा का पहला चरण है।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने से राज्य में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आयेगी। यह राज्य के हित में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब खेती के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम होगी। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम के नारे को भाजपा की सरकार ने साकार करने का प्रयास किया है। आज देश में कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/6 को योगदान देती है तथा हमारी जनसंख्या का मुख्य हिस्सा जीविका के लिए इसी पर निर्भर है। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए इसे तकनीक से जोड़ने की जरूरत है। वर्तमान में कृषि को व्यवसायिक बनाने के लिए आधारभूत संरचना,आधुनिकीकरण सरकारी व निजी दोनो प्रकार के निवेश बढ़ाये जाने की तत्काल जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, पूसा इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में आज़ादी के बाद इस तरह के संस्थान और नहीं स्थापित किये गये। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में ऐसी दो संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के हित में उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है। किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का समय होता है, जब उसके उपज को उचित मूल्य नहीं मिलता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ किसान अपने उत्पादन का मूल्य तय नहीं करता है, बल्कि खरीददार ही फसल का मूल्य तय करता है। इस मूल्य की अस्थिरता से किसानों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की राशि की व्यवस्था की है। किसानों का साथी होता है पशु, जिससे किसान खेती करता है और खेती के काम में लेता है। पशुपालन करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। गौ-पालन से किसान अपने परिवार का पोषण करता है। इस प्रकार पशुपालन खेती की रीढ़ है। भारत के वातावरण में विदेशी नस्ल की गाये बहुत उपयोगी नहीं होती है। अतः हमारी सरकार ने देशी पशु नस्लो के विकास के लिए 50 करोड़ रूपये का फंड रखा है। इसी के साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर नीली क्रांति की शुरूआत करने जा रही है। किसानों की दूसरी बड़ी समस्या होती है भण्डारण की। भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को अपना अनाज़ ओने-पोने दाम पर बेचना पड़ता है, जिसके कारण हमारे किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े हैं। यह सुन मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। जब हमारे अन्नदाता ही भूखे रहेंगे तो इस देश का क्या होगा। इस समस्या को देखते हुए हमारी सरकार ने कृषि ऋण, अल्पावधिक फसल ऋण, ग्रामीण संरचना के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण उत्पादक विकास और उत्थान निधि, भूमिहीन किसानों के लिए संयुक्त कृषि समूहों के लिए 5 लाख के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। नई खेती तकनीकों जैसे- जल संरक्षण, जैविक खेती आदि संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए किसान टी.वी. शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है किसान। अन्नदाता सुखी भव नारे के साथ मैं अपनी सरकार की ओर से किसानों को आश्वस्त करता हूँ कि कृषि में 4 प्रतिशत विकास दर बनाये रखने के लिए वचनबद्ध हैं।

100 स्मार्ट सिटी के लिए 7060 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर भारत विश्वस्तरीय शहरीकरण की ओर बढ़ेगा। सभी के लिए स्वास्थ्य के तहत नःशुल्क दावा सेवा और नःशुल्क जाँच सेवा प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी द्वारा एम्स जैसे 4 नये संस्थान खोलने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। ग्रामीण भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 15 मॉडल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी, जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू टीचर प्रोग्राम की शुरूआत हुई है। पांच नये आई.आई.टी. और पांच नये आई.आई.एम. की स्थापना गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा युवाओं के सपनों को साकार करेगी। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत से गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जायेंगे। राष्ट्रीय इंटरनेट एवं तकनीकी मिशन भी शुरू किया जायेगा। सबके लिए वर्ष 2022 तक सरकार सबके लिए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने जहां होम लोन पर टैक्स में छूट दिया है, वहीं नेशनल हाउसिंग बैंक को 4000 करोड़ भी उपलब्ध कराये हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में रोज़गार उन्मुखता एवं उद्यमिता एवं उद्यमिता विकास के लिए स्किल इण्डिया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। यह योजना पारम्परिक व्यवस्थाओं को भी प्रशिक्षण देगा। शारीरिक रूप से नःशक्तजनों के लिए संस्थानों में सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनको समान अवसर मिल सकें।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना के तहत बालिकाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये। इस बजट में आधारभूत संरचना पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

सड़क परिवहन के साथ-साथ शिपिंग और नये एयरपोर्ट भी विकिसत होंगे। गंगा नदी पर जलमार्ग का विकास करना है। यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से ये परियोजनाएँ भारत को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनायेगी। बजट में पांच पर्यटन सर्किट बनाने के निर्णय से रोज़गार सृजन से युवाओं को काम मिल सकेगा।

वन रैंक-वन पेंशन से सैन्य बल आधुनिकीकरण एवं मेमोरियल की स्थापना के प्रावधान से भारतीय सेना का मनोबल ऊँचा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी।

नदियों को जोड़ने की योजना की शुरूआत से देश में सूखा और बाढ़ की समस्या से निज़ात मिलेगी। हमारी सरकार महत्वपूर्ण खेलों के लिए देश के विभिन्न गांवों में राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी बनायेगी। यह अकादमी अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं से पूर्ण होंगी।

यह बजट उद्योग जगत से लेकर गांवों के किसान, युवाओं, महिलाओं के हित में बनाया गया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ.

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2014-15 निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। गत कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अत्याधिक गिरावट देखी गई है। जो उपाय वित्त मंत्री जी ने घोषित किए हैं, वे मुद्रास्फीति के निम्न स्तर, निम्न राजकोषीय घाटे एवं नियंत्रणीय चालू खाता घाटे सहित आर्थिक स्थायित्व के साथ-साथ अगले तीन चार वर्षों में 7-8 प्रतिशत की वृद्धिदर बनाए रखने की शुरूआत है। जब उच्च वृद्धि अनिवार्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोगों की अपेक्षाएं काफी अधिक है इसलिए हम और प्रतिबद्ध होकर मजबूत भारत के सृजन में कोई कसर नहीं रखेंगे। हमें अच्छी तरह याद रखना होगा कि वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद दर 5.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 4.9 प्रतिशत एवं वर्ष 2013-14 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट अधिक राजस्व जुटा कर नहीं बल्कि व्यय में कटौती करके प्राप्त की गई थी। व्यय में कटौती करके राजस्व घाटे को कम करना समस्या का समाधान नहीं है। अतः मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार ""सबका साथ सबका विकास"" का ध्यान रखकर इस समस्या का उचित समाधान करेंगे। राजकोषीय घाटे को कम करने का जो रोड़मैप है, वर्ष 2015-16 में 3.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में 3 प्रतिशत पर लाना अत्यंत सराहनीय कदम है। आपने अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने का जो भरोसा दिलाया है उससे निश्चित रूप से इनका जीवन और सुखमय होगा। आपका राज्यों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के बारे में आश्वस्त किया जाना अति उत्तम कदम है। आपका निवेशक समुदाय को आश्वस्त किया जाना और उनको यह समझाना कि हम ऐसी स्थायी और भावी करारोपण योजना की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जो निवेशकों के अनुकूल और विकास प्रेरक होगी। इससे निश्चित रूप से भारतीय एवं विदेशी निवेशक समुदाय हमारे कर प्रशासन पर विश्वास करेगा और देश के विकास में भागीदार होगा। साथ ही साथ आपके प्रशासनिक और कानूनी कदलाव करने के फैसले से चार लाख करोड़ से अधिक कर की मांग संबंधित मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। इससे करदाताओं के मुकदमों संबंधित चिंताओं का समाधान निकलेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित होगी।

स्मार्ट शहरों के निवास का खर्चा जो नव-मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग को आवास के साथ-साथ समस्त शहरी व्यवस्था प्रदान करेगा और इसके निर्माण के तीन वर्ष के लॉक इन के चलते एफडीआई के

लिए क्षेत्र और पूंजी की अपेक्षा को क्रमशः 50 हजार वर्गमीटर से घटाकर 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्र तथा 10 मिलियन अमेरिकन डालर से घटाकर 5 मिलियन डालर करने से स्मार्ट शहरों के निर्माण में तेजी आएगी। वित्त मंत्री जी का सुझाव है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे सरकार खुदरा शेयरों की बिक्री से धन जुटाएगी जिससे वित्तीय स्थिरता निश्चित आ पाएगी। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को पूंजीगत निवेश के जरिए 247,941 करोड़ रूपये की धनराशि देने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक सृजन एवं स्थिर होंगे। इसके अतिरिक्त स्मार्ट शहर का निर्माण, ई-वीजा से देश के नागरिकों को आसान एवं अत्यधिक सुविधा मिलने जा रही है। किसान विकास पत्र से बैंक बचतों में निवेश करने वाले लोगों को अधिक बढ़ावा मिलेगा। दक्ष भारत युवाओं और गरीबों के उद्यम कौशल को और अधिक बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से मानसून पर निर्भरता में कमी आएगी जिससे किसानों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

वर्तमान सरकार अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु इनके युवा उद्यमियों को आईएफसीआई द्वारा ऋण उपलब्ध कराने से उनको अधिक स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को पुर्नजीवित करने का प्रयास एवं प्रस्ताव सराहनीय है। विकलांग एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी प्रोत्साहन की योजना बनी है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना से बेटियों के प्रति कुछ लोगों की उदासीनता समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। मनरेगा से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सोच प्रशंसनीय है।

वित्त मंत्री जी की सोच "सबके लिए स्वास्थ्य" तथा इस हेतु निशुल्क औषधि सेवा के शुरू किए जाने से स्वस्थ भारत की परिकल्पना की जा सकती है। डिजीटल भारत का सपना गांव एवं शहर की दूरी कम करेगा। सूक्ष्म, मझौले, मध्यम उद्यम क्षेत्रों के विकास से कमजोर तबके के लोगों को लाभ मिलना स्वभाविक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु इस बजट में जोर दिया है तथा कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके सुझाव स्वागत योग्य है। इस बजट में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है तथा इसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा हेतु बजट को 2013-14 की तुलना में बढ़ोतरी किए जाने से पुलिस बलों के प्रोत्साहन में बढ़ोतरी होगी, नदियों को जोड़ने से सिंचाई तथा पेयजल की समस्याओं से निदान मिलेगा। गंगा संरक्षण घाटों का विकास सराहनीय योजनाएं है। खेल के प्रति पिछली सरकार का रवैया उदासीन रहा है। वित्त मंत्री जी योजनाओं से देश में खेल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खिलाड़ी अधिक प्रोत्साहित होंगे।

पिछली यूपीए सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी में जो टैक्स के रूप में पचास लाख करोड़ का अतिरिक्त भार हम पर पड़ा है, उसे लौटाना पड़ेगा। आज विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार भारत है तथा खरीददार भी भारत है। आज भी हम 70 प्रतिशत माल विदेशों से खरीदते है, चाहे फर्टीलाइजर हो, तेल हो या पॉवर लिंकेज हो। यह हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं जिसकी बदौलत हम देश का ढांचा बनाए रखते हैं। यह हमारी 70 प्रतिशत मूल खरीददारी है। वर्तमान सरकार की सोच है थोड़ी पूंजी, आय अधिक। हम टेक्नोलोजी (तकनीकी) क्षेत्र में भारत को उभारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी के माध्यम से जो आज कहीं ना कहीं टेक्नोलोजी में विदेशी नियंत्रण में है, इसी तकनीकी को हम आगे ले जाकर भारत का नियंत्रण करवाना चाहते हैं, इसी हेतु वित्त मंत्री जी ने बजट में डिफेंस में 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव किया है जो स्वागत योग्य है। यह कैसे हो कि हम गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचने की क्षमता हो जो सौ फीसदी तक होने का इरादा रखते हैं।

आज हमारा होल्डिंग केपीटल 51 फीसदी है, इसे 90 से 100 फीसदी तक पहुंचाने की सोच माननीय वित्त मंत्री जी की है जो महत्वकांक्षी सोच है। नई योजना कैसे बने इसके लिए मूल सोशल सेक्टर को बदलने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सोशल सेक्टर से जितना लाभ गरीब, पिछले, दलित, अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी तथा रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा तथा देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। विगत 10 वर्षों में उत्पादन कम होने के कारण कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों एवं युवाओं की नौकरी पर पड़ा, उसकी आमदनी पर पड़ा, टैक्स पर भी प्रभाव पड़ा। मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग है जो लंबी सोच और भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करता है, उसकी सोच को हमारे वित्त मंत्री जी ने उनको 100 प्रतिशत इन्सेन्टीव देने का साहसिक निर्णय किया है। वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने हेतु तथा भारत को संपूर्ण रूप से विकसित करने हेतु आने वाले निवेशकों के कर में छूट का प्रावधान रखा है। आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पावर और एनर्जी जेनरेट हो तथा देश के संपूर्ण विकास में सहायक हो। बजट प्रस्ताव में मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में जो ड्यूटी लगाई जाती थी, उसको कम करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को कम करने का निर्णय साहसिक एवं सरकार का सराहनीय कदम है। इस बचत के माध्यम से वह अपने घर का सपना देख सकता है, पढ़ने का सपना देख सकता है तथा ब्याज के फायदे उठा सकता है। ईएमआई के माध्यम से आवासी ऋण को कम किया गया है ति 0 प्रतिशत पर करने की संभावना भी मंत्री जी ने जताई है। यूपीए सरकार में 14 प्रतिशत की दर से हाउसिंग लोन होने के कारण आम व्यक्ति के घर का सपना 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ।

अतः वर्ष 2014-15 का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अत्यंत प्रशंसनीय एवं स्वागत योग्य है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की सोच को पूरी तरह देखा जा सकता है।

*श्री रामसिंह रावत (छोटा उदयपुर)- भारतीय लोकतांत्रिक शासन के 67 साल के इतिहास की एक अविरल और विलक्षण घटना है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ राजग की गठबंधन सरकार। श्री नरेन्द्र मोदी जी के अच्छे दिनों की और सुशासन के शुभारंभ की घटना निश्चित ही शुभ और श्रेयस्कर है। जिस तरह से हमारा गुजरात, हमारा इसलिए की मैं गुजरात के छोटा उदयपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गुजरात एक सबसे सफल, सबसे धनी, सबसे उन्नत और शांतिपूर्ण राज्य है। पूरे राज्य को श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकालों में इन स्थितियों तक पहुंचाया है। अब वही सफलता, वह शांति, वही आर्थिक विकास, वही उन्नति और वही जन-जन के उन्नयन का स्वप्न सम्पूर्ण राष्ट्र में चरितार्थ होते हुए देखेंगे। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने नःस्वार्थ व्यक्तित्व, अपने ओजस्वी कर्मों, अपने निश्छल प्रेम और उन्नत भारत के स्वप्न के द्वारा करोड़ों लोगों का दिल जीतकर एक आशा और विश्वास का वातावरण बनाया है। वे कर्मठ एवं जीवट वाले व्यक्तित्व है, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत उन्नति के नये शिखरों पर आरूढ़ होने को तत्पर है। इसकी आहट हाल ही में प्रस्तुत रेल बजट और आम बजट में सुनाई दी है। आम बजट ने देश की जनता के हृदय में आशा की उम्मीदें जागृत की है। मेरी दृष्टि में चरमरायी हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए एक संजीवनी और सर्वोदय के रूप में आया है। यह बजट भारत को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध एवं आश्वस्त है। यह गरीबों तथा समाज के वंचित तबको के लिए उम्मीद की एक किरण है। मेरा विश्वास है कि यह बजट भारत को न केवल तरक्की की नई ऊँचाईयों पर पहुंचायेगा बल्कि सरकार के उद्देश्यों से विश्व में भारत की एक अलग छवि का निर्माण होगा।

वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने हज़ारों करोड़ रूपयों का प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों, गंगा नदी परियोजना, खेल विश्वविद्यालय, पूर्ण स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एम्स, आई.आई.एम., कृषि के लिए बुनियादी ढांचे के लिए कोष, मदरसों का आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास कोष, मौसम सुधार का बुनियादी ढांचा, युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय, मथुरा और आगरा जैसे शहरों की विरासत सुरक्षित रखने और नदियों को जोड़ने आदि के लिए किया है। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि एन.डी.ए.

सरकार को देश की अर्थव्यवस्था बेहद ही खराब हालत में मिली है। यद्यपि सरकार सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात की संभावना है कि मौजूदा आर्थिक हालात और खराब मानसून नई सरकार को ऐसा करने की अनुमति न दे। इस परिदृश्य में भी नई सरकार अगले तीन-चार वर्षों में 7-8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प रखती है, जिसके लिए अधिक संसाधनों को पैदा करने की जरूरत है। यद्यपि 4.1 प्रतिशत के राजस्व घाटे का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में खर्चों पर नज़र रखने के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा और सब्सिडी की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी। खासतौर पर खाद्य और तेल सब्सिडी की समीक्षा होगी। कश्मीरी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इन कदमों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये फिलहाल प्रारंभिक कदम हैं और दिशापूर्ण भी हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट में रक्षा के लिए 2.29 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान है और बीमा तथा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। श्री अरूण जेटली जी का यह पहला बजट है, जो पूरी तरह से संतुलित है। उसका फोकस 100 स्मार्ट शहरों, विदेशी निवेश, सब्सिडी प्रबंधन आदि पर है। यह प्रशंसनीय है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वित्तीय अनुशासनहीनता की बुराईयों की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी और समाज के सभी वर्गों, खासतौर पर भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित होगा।

विचारों और सामग्री से भरा यह एक मिला-जुला बजट है। जिसमें एन.डी.ए. सरकार की मंशा और दिशा अच्छी दिखाई देती है। यह उम्मीदों से भरा बजट है। करों की दरें नीचे करने और टैक्स का दायरा बढ़ाना, राजस्व एकत्र करने के लिए प्रगतिशील कदम है, जिससे उद्योगों के विकास के लिए टैक्स फ्रेण्डली माहौल बनेगा। अब समय आ गया है कि बाह्य दबावों से अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से बचाकर पिछले दो सालों के विपरीत भारत की विकास दर को गति दी जाए। यद्यपि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य के बजटों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत होगी। राज्यों को ई-प्रणाली स्थापित करने और उसने बनाए रखने में सहायता करने के साथ ही ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन भाजपा की नई सरकार से यह उम्मीद करना कि वह एक ही महीने में ठोस योजनाओं के साथ आगे आ जाये या सभी समस्याओं को तुरंत हल कर दें तो यह खुद को भुलावे में रखने जैसा होगा।

देश ने 67 सालों में जितना विकास करना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पाया। अब अवसर सामने है और इसके शुभ संकेत इस बजट में दिखाई देते हैं। यदि निवेशकों (घरेलू या विदेशी) का विश्वास भी बहाल हो जाए तो आधी समस्या तो यूं ही हल हो जाएगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह बजट सरकार में समाज के सभी वर्गों का विश्वास बहाल करेगा।

दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थॉमस पेन ने कहा था- " हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम विश्व को पुनः आरंभ कर सकते हैं। " मैं यहां विश्व को पुनः आरंभ करने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत का विकास और अभ्युत्थान निश्चित ही आरंभ हो चुका है। गांधी और नेहरू के बाद राष्ट्रीय नेताओं के कदम छोटे होते गए और परछाईयां बड़ी होती गई। आज के तीव्रता से बदलते समय में हमें अपनी और राष्ट्रीय जीवन प्रणाली की रचना करनी है। लोकतंत्र श्रेष्ठ प्रणाली है पर संचालन में शुद्धता और पवित्रता हो, जनभावना लोकतंत्र की भावना होती है, लोक सुरक्षित रहेगा तभी तंत्र सुरक्षित रहेगा।

मुझे विश्वास है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक मंगल होगा और लोकतंत्र को शुद्ध साँस मिलेगी। लोक जीवन और लोक तंत्र की अस्मिता को गौरव देने के शुभ दिन आ गए हैं। आओ मिलकर देश को तरक्की की ओर अग्रसर करें।

***श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र)-** मैं आम बजट 2014 का समर्थन करता हूँ। पहली बार किसी भी सरकार ने इतना संतुलित बजट पेश किया है। इसमें समाज के सभी वर्गों एवं देश के सभी राज्यों का ख्याल रखा गया है। कह सकते हैं कि यह पूरे देश का बजट है।

बिहार में आई.आई.एम. खोलने तथा भागलपुर में टेक्सटाईल मेगा क्लस्टर के प्रस्ताव की घोषणा का स्वागत करता हूँ। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 89 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। यहां भूमिहीन किसानों की काफी संख्या है। बिना भू-स्वामित्व के उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता है। जिसके कारण वे ऊँचे ब्याज दर पर बाज़ार से लोन लेते हैं और कर्ज के चंगुल में फँस जाते हैं। इससे बचाने के लिए नाबार्ड द्वारा भूमिहीन किसान के संयुक्त कृषि समूहों को 5 लाख के धन की व्यवस्था के प्रस्ताव का

स्वागत करता हूँ। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना मील का पत्थर साबित होगी।

बिहार में भंडारण की क्षमता नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन काफी बर्बाद होता है। पूरे देश में वैज्ञानिक भण्डारागार के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रूपए आवंटित किया गया है, जिससे किसानों का काफी फायदा होगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी।

अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी जीविका उर्पाजन के लिए पुश्तैनी कला पर निर्भर हैं। उनकी इस कला को जीवित रखने और उसमें वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण संवर्द्धन हेतु कार्यक्रम की शुरूआत करने की घोषणा का स्वागत करता हूँ। साथ ही मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि के आवंटन का भी स्वागत करता हूँ।

प्रधानमंत्री जी का देश में स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना है। उससे देश में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। वित्त मंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण की घोषणा की है। मेरी मांग है कि बिहार में अधिक से अधिक स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाये। बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है। वहां मात्र 11 प्रतिशत ही शहरीकरण है। इस योजना से सभी सेक्टरों के विकास में तेजी आयेगी।

मैं बिहार के विकास के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूँ। बिहारवासियों का मानना है कि जब तक बिहार के 10 करोड़ 38 लाख लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास पूरी तरह संभव नहीं है। उत्तरी बिहार बाढ़ से तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। नदियों को जोड़ने की योजना में बिहार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पड़ोसी देश नेपाल से प्रत्येक साल बिहार को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। अगर भारत सरकार इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मान कर पहल करे तो बिजली का भी उत्पादन होगा और बिहार बाढ़ से भी बचेगा।

बिहार में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। हालांकि बुद्ध सर्किट के विकास की घोषणा से पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी। जैन सर्किट और सूफी सर्किट की भी अपार संभावनाएं हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये।

बिहार में बिजली की भारी समस्या है। बरौनी, कांटी, बाढ, नवीनगर, पीरपैंती बिजली परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण कराया जाये। पटना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेन्टर की स्थापना की जाये।

पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाये, जहां कारगो की भी सुविधा हो। बिहार में गया और मोतिहारी में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लायी जाये। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये। बिहार में नये इंजीनियरिंग, मेडिकल और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं को जल्द पूरा करने की दिशा में गंभीर प्रयास किये जाये।

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा)-** माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर बहस में कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय बजट भारत के चतुर्दिक विकास की आधारशिला है। भारत की जनता ने परिवतन के लिए निर्णायक मत दिया है। यह बजट परिवर्तन की दिशा में उप्रेरक होगा। इससे रोज़गार सृजन, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और सुशासन की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह निर्णायक बजट है।

भाजपा शासन का यह प्रथम बजट कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का मूर्तरूप है, जो यह बताता है कि शासन को जहां सबकी चिंता करनी चाहिए, वहीं करों के संग्रहण में मधुमक्खी जिस तरह हर पुष्प से बिना उसको क्षति पहुंचाये शहद का संग्रहण करती है, उसी प्रकार शासन को भी जनता से कर संग्रहण करना चाहिए। साथ ही यह बजट गरीब, किसान, भूमिहीन, मज़दूर, पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला, युवा, बुजुर्ग एवं ग्रामीण भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर विकास के अंतिम कतार पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का साकार रूप है। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत 2014-15 का यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित- " सबका साथ-सबका विकास " नारे के प्रति प्रतिबद्धता का कार्यरूप है। यह बजट आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक शक्ति का केन्द्र बनाने की यात्रा का प्रारंभिक चरण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री Mr. Joseph Stiglitz का यह कहना है कि किसी देश की प्रगति का आंकलन उसके जी.डी.पी. के वृद्धि दर से नहीं होता है। बल्कि उस देश का जनसाधारण कितना खुश है, उससे होता है। इस कसौटी पर यह बजट जी.डी.पी. के वृद्धि दर से आगे भारत को खुशहाल बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। ख्.D.घ्. से G.D.H. (Gross Domestic Happiness) की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरूआत है।

इस केन्द्रीय बजट ने पहली बार चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादों को साकार करने का साहस किया है। जनता ने जिस एजेंडा को भारी समर्थन देकर भाजपा को शासन की बागडोर सौंपी है, उसको पूरा करने का संकल्प दिखता है इस बजट में। इसमें प्रमुख उदाहरण क्रमशः ये हैं- भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई की रोकथाम के लिए कीमतें स्थिर करने के लिए कोष का गठन, टैक्स की प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाना, पर्यटन को बढ़ावा, महिला सशक्तीकरण, रोज़गार रहित विकास का अंत, आई.टी. सेक्टर का विकास, बुनियादी ढाँचा निर्माण, कृषि को प्रोत्साहन, पूर्वोत्तर और हिमालयन राज्यों का विकास, पवित्र नदी गंगा और नदियों का संरक्षण, नए शहर इत्यादि प्रमुख है। भविष्य में अन्य दलों पर यह दबाव होगा कि वे अपने घोषणा-पत्र में सोच-समझकर संतुलित बनाये और उस पर अमल करे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि के क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन का वाहक होगी। खेती के लिए किसानों की मानूसन पर निर्भरता कम होगी।

झारखंड जैसे प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना से खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाये रखने की प्रतिबद्धता के साथ ही कहा गया है कि द्वितीय हरित क्रांति लायेंगे और " प्रोटीन क्रांति " के क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। प्रोटीन क्रांति से तात्पर्य दलहन की खेती से है। माननीय जेटली जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि चतरा लोक सभा के अंतर्गत पड़ने वाले जिले चतरा, लातेहार और पलामू दलहन उत्पादन का क्षेत्र है। सरकारों की उपेक्षा से

दलहन की खेती मृत्यु के कगार पर है। अगर इस क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुआ तो देश को दाल के आयात के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और हमारी विदेशी पूँजी अक्षण्णु बनी रहेगा। खेती को बढ़ावा मिलने के चलते गांव और गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। 100 नई मोबाईल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खुलने से किसानों को लाभ होगा। " भूमिहीन किसान योजना " के तहत ऋण की उपलब्धता से भूमिहीन किसानों को लाभ होगा। " मूल्य स्थिरीकरण कोष " के निर्माण से कृषि उत्पाद का सही दाम मिलने में किसानों को सुविधा होगी।

भारतीय पशु नस्ल विकास एवं मत्स्य विकास के लिए परियोजना की शुरूआत से ग्रामीण क्षेत्रों की आय वृद्धि होगी। कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाने से किसान को लाभ होगा।

भंडारण संरक्षण कोष कृषि उत्पादन को बचाने में सहायक होगा। नई यूरिया नीति बनाने से किसान को राहत मिलेगी। किसान टी.वी. कृषि संबंधित आधुनिक व वैज्ञानिक जानकारियां किसानों तक पहुंचाने में लाभकारी सिद्ध होगा।

" श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू-अर्बन " ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की भांति नागरिक संरचना एवं उनसे संबंधित सेवाएँ शुरू कर ग्रामीण जीवन स्तर को शहरों के समकक्ष बनायेंगे। " दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाधित बिजली हर घर को उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। " स्वच्छ भारत अभियान " ग्रामीण भारत को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करेगा। " प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ", " आजीविका एन.आर.एल.एम., वाटर शेड प्रबंधन, पंचायती राज, स्वच्छ पीने का पानी इन मदों में बजट की वृद्धि ग्रामीण भारत की उन्नति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आदिवासी कल्याण के लिए " वन बंधु कल्याण योजना " झारखंड जैसे राज्य में आदिवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लायेगा। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बजट में भारी वृद्धि के साथ ही उनके लिए उद्यमिता विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने से देश में नये मध्यम वर्ग में उनकी सहभागिता बढ़ेगी।

100 स्मार्ट सिटी के लिए 7060 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर भारत विश्व स्तरीय शहरीकरण की ओर बढ़ेगा। " सभी के लिए स्वास्थ्य " के तहत नःशुल्क दवा सेवा और नःशुल्क जांच सेवा प्रदान करना इस बजट की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी द्वारा एम्स जैसे 4 नये संस्थान खोलने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार झारखण्ड सहित सभी राज्यों में एम्स के समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी। ग्रामीण भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 15 मॉडल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करेगी जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

पंडित मदन मोहन मालवीय न्यू टीचर प्रोग्राम की शुरूआत हुई है। पांच नये आई.आई.टी. और पाँच नये आई.आई.एम. की स्थापना गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा युवाओं के सपनों को साकार करने में सक्षम होगी। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरूआत से गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट एवं तकनीकी मिशन की शुरूआत गांवों और स्कूलों में होगी। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जायेगा। सबके लिए घर वर्ष 2022 तक सरकार सबके लिए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने जहां होम लोन पर टैक्स में छूट दिया है, वहीं नेशनल हाउसिंग बैंक को 4000 करोड़ रूपए भी उपलब्ध कराये हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में रोज़गार उन्मुखता एवं उद्यमिता विकास के लिए " स्किल इण्डिया प्रोग्राम " शुरू किया जा रहा है। यह योजना पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी पूशिक्षण देगा। शारीरिक रूप से नःशक्तजनों के लिए विशेष संस्थानों एवं सुविधाओं का प्रावधान किया गया है ताकि उनको समान अवसर मिल सकें।

" बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ " योजना के तहत बालिकाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस बजट में आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़क परिवहन के साथ-साथ शिपिंग और नये एयरपोर्ट भी विकसित होंगे। गंगा नदी पर " जल मार्ग विकास " योजना इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 कि.मी. दूरी का बनेगा। जो छः वर्षों में पूरा होगा, जिसकी लागत 4200 करोड़ रूपए होगी। यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से ये परियोजनाएँ भारत को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनायेंगी। वहीं बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के द्वारा खनिज की रॉयल्टी दरों में संशोधन किये जाने के आश्वासन से झारखण्ड को विशेष फायदा होगा। झारखण्ड प्रदेश अपने खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन की मांग वर्षों से करता आ रहा है।

बजट में पांच पर्यटन सर्किट बनाने के निर्णय से झारखण्ड राज्य को जहां पर्यटकों से अतिरिक्त राजस्व एवं आय की प्राप्ति होगी, वही रोज़गार सृजन के माध्यम से युवाओं को काम मिल सकेगा। इस योजना का लाभ झारखण्ड में स्थित ज्योर्तिलिंग, वैद्यनाथ धाम (देवघर) इटकोरी, कातेश्वरी (हण्टरगंज), मधुबन, पारसनाथ, जीवाश्म पार्क सहित झारखण्ड के अन्य पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी।

" वन रैंक- वन पेंशन " सैन्य बल आधुनिकीकरण एवं वार मेमोरियल की स्थापना के प्रावधान से भारतीय सेना का मनोबल ऊँचा होगा और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर आंतरिक सुरक्षा के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने से पूरे देश में अमन चैन व शांति स्थापित करना आसान होगा। " राष्ट्रीय पुलिस स्मारक " के निर्माण से पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि होगी। पुलिस आतंकवाद, उग्रवाद आदि की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी।

हिमालयन प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए खेलों के प्रोत्साहन के लिए विशेष योजना बनाई गई है। अरूण प्रभा योजना पूर्वोत्तर भारत के लिए चालू की जायेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए विशेष सुविधा दी जायेगी।

नदियों को जोड़ने की योजना की शुरूआत से देश में सूखा और बाढ़ की समस्या से निज़ात मिलेगी। विस्थापित कश्मीरियों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान भारत की एकात्मकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। युवाओं के लिए यंग लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जायेगा। युवाओं के लिए रोज़गाररहित विकास की अब तक की अवधारणा को समाप्त कर रोज़गारोन्मुख विकास हेतु शुरूआत हुई है। सरकार महत्वपूर्ण खेलों के लिए देश में विभिन्न गांवों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी बनायेगी। यह अकादमी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से पूर्ण होगी।

टैक्स को तर्कसंगत बनाने के लिए टैक्स नीति में सुधार कर उसे आसान बनाना, अप्रत्यक्ष हस्तांतरण की श्रेणी में 2012 में हुई पिछली तारीख से संशोधन से संबंधित नए मामलों की जांच के लिए सीबीडीटी की सहमति से उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई है, जबकि नःशक्त और विकलांगों की सुविधा व कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इस साल के अंत तक पूरे देश में जी.एस.टी. लागू हो जायेगा। व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हज़ार कर दी गयी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो लाख पचास हज़ार रूपए से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गयी है। 80 सी में छूट 1 लाख से 1.5 लाख कर दी गयी है। हाउसिंग लोन में छूट 1.5 लाख से दो लाख कर दी गयी है। करों के भुगतान को लेकर लगभग 4 लाख करोड़ रूपए के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधायी एवं प्रशासनिक परिवर्तन की घोषणा किये जाने के लिए वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इससे सामान्यजनों को लाभ पहुंचेगा। एक्साईज व कस्टम ड्यूटी में छूट देकर भारतीय उद्योग व निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय उद्योग जगत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।

चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत झारखण्ड का चतरा, लोहरदगा जिला और पलामू जिले का एक विधान सभा क्षेत्र आता है। यह पूरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। सर्वविदित है कि झारखण्ड के ये तीनों जिले अतिउग्रवादी गतिविधियों के लिए चिन्हित क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देश के विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस क्षेत्र में कोयला, एल्यूमिनियम, बॉक्साईट, डोलामाईट एवं अन्य खनिज संपदा है। वन उपज और कृषि उपज विशेषकर दलहन उत्पादन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सौन्दर्य एवं मानव संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र देश के उन्नत क्षेत्रों के समकक्ष है, परंतु आज तक विकास की जो दिशाहीन यात्रा रही, उसके कारण यह क्षेत्र आज भी आज़ादी से पूर्व की स्थिति में ही खड़ा है। इसे प्रतीक्षा है कि एक ऐसे विकास पुरूष और एक ऐसी सरकार का जो राजनैतिक दबाव समूहों से परे आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्धता के अनुरूप देश के सभी क्षेत्रों का एक रूप विकास कर सकें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाने की कृपा करें कि विकास के अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति और क्षेत्र तक पहुंचना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि हम भारतीय वित्त प्रबंधन की भारतीय शैली को विकसित करें। हम GDH (सकल घरेलू खुशहाली) को मापने की नई पद्धति की शुरूआत करें। हमें अपना " तीसरा पथ " (Third Way) आर्थिक विकास के लिए विकसित करना होगा। जिसकी शुरूआत आपने इस बजट से की है।

माननीय वित मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तावित यह बजट जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित " एकात्म मानव दर्शन " के केन्द्र बिन्दु विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति के उदय के प्रति प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर अपने विभिन्न बजटीय प्रावधानों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना को भी साकार करता है। भारत को Global Power और एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हमारा अभियान माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में " सबका साथ- सबका विकास मंत्र के साथ परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ हो गया है। यह बजट उसी दिशा में प्रारंभिक चरण है।

अंत में कहना चाहता हूँ कि-

"" कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता।

एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद)- सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि देश की विषम आर्थिक परिस्थितयों पर नियंत्रण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निदेशन में भारत वर्ष के लोगों का दिल जीतने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट की प्रशंसा देश के प्रत्येक गरीब, किसान, व्यापारी, मेहनतकश मजदूर, उद्यमी, व्यापारी, बुजुर्ग, विकलांग, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग तथा आम लोगों ने की है।

यू.पी.ए. सरकार ने भारत का विकास अस्थिर, असंतुलित, असमन्वित तथा अप्रोत्साहित कर दिया था। जिसके कारण भारत के लोगों की कई तस्वीर बन गई। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता गया। लुभावने नारे देकर लोगों के वोट लेती रही। कभी गरीबी हटाने के नाम पर तो कभी श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद टुअर होने के नाम पर, कभी अमेरिका से न्यूक्लियर समझौता के नाम पर, कभी एक सौ दिन में महंगाई घटा देने के नाम पर तो कभी आम लोगों की बात जैसे लुभावने नारे देती रही। देश की आर्थिक संतुलन की स्थिति यह है कि देश में किसी प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 40 हज़ार प्रति व्यक्ति है तो किसी राज्य में 2 लाख रूपये है। बाज़ार एक है, वस्तुओं के दाम देश में एक है, लेकिन आमदनी भिन्न है।

भारत में कृषि योग्य भूमि का 64 प्रतिशत मानसून पर निर्भर करता है, सिंचाई का कोइ प्रबंध नहीं है। वर्तमान बजट मे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का निर्णय लेकर वित मंत्री जी ने देश और किसान के हित में बड़ा निर्णय लिया है।

मध्यम वर्ग को आयकर में 50 हज़ार रूपये का स्लेब बढ़ाकर तथा बुजुर्गों के लिए 3 लाख की सीमा कर काफी आशीर्वाद लिया है। मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन के ब्याज पर आयकर में छूट, सोलर लाइट को सस्ता, गरीब के जूते, मोबाइल आदि जैसी वस्तुओं को सस्ता कर गरीब का हृदय जीतने का काम किया है। अटल जी के सपनो को साकार करने के लिए नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करना बहुत बड़ा कदम है। गरीबों के घर में बिजली, शुद्ध पेयजल, छात्राओं के लिए विद्यालय में पानी, शौचालय की व्यवस्था, गरीबों के लिए दीनदयाल आवास योजना, शहरों के विकास के लिए योजना जैसे अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

मैं धनबाद लोक सभा क्षेत्र जो झारखण्ड राज्य में आता है। इसकी समस्याओं की ओर वित मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

धनबाद जिले में सिन्दरी का खाद कारखाना बंद पड़ा है। यह स्थान दामोदर नदी के किनारे है तथा मुश्किल से 2 कि.मी. पर कोयला का अपार भंडार है। जमीन की कमी नहीं है। आधारभूत संरचनायें काफी सुदृढ़ है। पिछली यू.पी.ए. की सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में यहाँ सेल के द्वारा स्टील प्लांट खोलने के लिए 34 हज़ार करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी, लेकिन दो वर्ष हो गये इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण हेतु 2008 में बोकारो जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिलान्यास किया, लेकिन आज तक यह कार्य संपन्न नहीं हो पाया। मेरे क्षेत्र में मिथेन गैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसके स्थानीय उपयोग हेतु कोई नीति नहीं बन पाई।

झारखण्ड में 42 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। धनबाद में एशिया का प्रतिष्ठित माइनिंग कॉलेज इण्डियन स्कूल ऑफ माइंस है, जिसे वर्षों से आई.आई.टी. का दर्जा देने हेतु मांग की जा रही है। सरकार इस पर ध्यान देकर आई.आई.टी. का दर्जा दे।

माननीय वित मंत्री जी झारखण्ड की बहुतायत भूमि खदानों में चली जाती है। आपने रॉयल्टी के दर को पुनः निर्धारण करने की बात कहकर झारखण्ड के लोगों में नई आशा जगाई है, इसके लिए आपके प्रति आभारी हूँ। आपने झारखण्ड में हॉर्टीकल्चर युनिवर्सिटी देकर इस राज्य के सम्मान को बढ़ाया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ।

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): I am extremely grateful to you for having me this opportunity to put forth my views on the Union Budget 2014-15.

Hon. Finance Minister has very rightly prioritized areas that would require more focus. It is indeed gratifying that agriculture happens to be one such area which has been accorded due importance in this Budget.

It understood the nature of problems afflicting the Indian economy are structural in nature. This Budget has pressed the accelerator in policy reforms in Defence, Insurance, Housing and Education.

A welcome move for crores of tax payers in the country was the FM's announcement of an increase in personal income tax exemption limit by Rs. 50,000 across all categories. Individual tax payers below the age of 60 years earning an amount up to Rs. 2.5 lakhs would now be exempted from paying income tax compared to earlier limit of Rs. 2 lakhs. In case of senior citizens above the age of 60 years, the exemption limit gets increased to Rs. 3 lakhs; an increase from the existing Rs. 2.5 lakhs.

The tax exemption limit has been hiked, the ceiling for saving enjoying tax concessions has been raised by 50%, the upper limit for deposits in the middle class-favoured Public Provident Fund (PPF) has been increased by 50% and for relatively better off among them, there is the increase in tax exempt interest payments on housing loans. In an attempt to boost household savings, the Finance Minister has announced an increase in exemption limit for investments under Section 80C of IT Act.

Foreign and domestic capital may not have got the "big bang" announcements they had hoped for, but there are many goodies for them in Budget 2014. For foreign capital there is the decision to further open up the defence production and insurance sectors and relax norms for real estate investment. For foreign institutional investors based in the country there is the decision to treat business income as capital gains. For all foreign companies operating in India there is the promise to be much more careful in applying Indian laws on retrospective taxation.

This budget is in the right direction for farming community. Agricultural growth target set at 4%. There is an urgent need to step up investment both Public and Private, in agro-technology development and creation and modernization of existing agri-business infrastructure. Our Government will work closely with the State Governments to re-orient their respective APMC Acts to provide for establishment to private markets.

This budget is providing every farmer with a soil health card to check any imbalance in fertilizer use and setting up of mobile testing labs, launching of a new Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana to improve access to irrigation in rain-fed areas. The Union Budget not only set a target of Rs. 8 lakh crore during 2014-15 towards rural credit, it introduced a Rs. 5,000 crore warehouse infrastructure fund.

By strengthening the value chain from production to distribution and marketing the budget addresses several core concerns, Creation of national markets, producer organizations and excise exemptions are welcome steps towards making farming more profitable and market-driven. To check volatility of food price, the budget announced a Rs. 500 crore price -stabilization fund. The budget also reiterated the present Government's commitment towards reforming the food sector. Restructuring FCI (Food Corporation of India) reducing transportation and distribution losses and efficacy of PDS (Public Distribution System) would be taken up on priority is welcome step.

This budget is remarkable plan for round-the-clock power. Power is a vital input for economic growth and our Government is committed to providing 24x7 uninterrupted power supplies to all homes. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana for feeder separation will be launched to augment power supply to the rural areas for strengthening sub-transmission and distribution system. Proposals for feeder segregation and distributed solar generation will improve the availability and quality of power supply in rural areas.

This budget set aside a sum of Rs. 100 crore for the need to convert employment exchanges into career centers for providing information about job availability. These centers will also extend counselling facilities to the youth for selecting the jobs best suited to their ability and aptitude.

This budget highlights the critical role that and educated and skilled workforce plays driving economic growth, significantly, the Government has taken steps to make education a quality-driven sector by beginning to shift the focus to outputs. It indicates the Government's intention to address the need for quality education for our youth.

The opening up of FDI will bring in opportunity for cheaper capital for smaller projects as well, improving quality and delivery of low cost and affordable housing projects. The announcement to set up a National Industrial Corridor Authority to coordinate the development of the industrial corridors, with smart cities linked to transport connectivity, will have a positive impact on the growth and development of the landlocked regions in the country.

Reduction of custom duty on LCDs and LEDs below 19-inch from 10% to 0%, will encourage local production. The incentives to invest in manufacturing will help increase the manufacturing base in India. It is a prudent move by the Government. The duty concession will help revive manufacturing of TVs in the SME (small and medium enterprises) sector and create employment opportunities.

Budget has put the roads sector on a fast track mode. An increase in the budgetary support to the roads and highways sector by 13.48 percent to Rs. 28,881 crore for the current financial year. The total plan outlay stands at Rs. 37,881 crore, including an internal and extra budgetary resource (IEBR) of Rs. 9,000 crore, according to the Budget documents. It looks like the finance ministry and the transport and highways ministry are collaborating with each other with the Finance Minister echoing the Transport Minister's roadmap to lay down 23km of road/highway everyday. This vision has been well augmented by the proposed infusion of funds into NHAI and the proposal to work on select expressways in conjunction with the development of industrial corridor.

The Government's energy security plans include harnessing renewable sources such as solar energy, biomass and wind power along with coal, gas, hydrometer and nuclear power to bring about an "energy revolution" in the country. The proposals for power sector presage a positive direction, to enhance energy security through renewable energy sources with both, large scale projects and distributed projects, and transmission lines connecting green energy corridors to load centres. The Government's focus on clean energy in the budget has been very holistic and, therefore, a step in the right direction that will provide strong impetus for the industry. Government has unleashed a flurry of schemes to educate, empower and protect women and the girl child and sensitize people to gender equality. The proposed Beti Bachao Beti Padao Yojna Scheme to improve to plight of the girl child, aims to increase awareness and focus on campaigns to sensitize people towards gender equality in India. A total amount of Rs. 100

crores has been allotted for the Beti Bachao Beti Padhao Yojana. The process of sensitization must begin early; therefore, the school curriculum must have a separate chapter on gender mainstreaming. Government attaches utmost importance to the welfare of girl child.

With these words, I support the Budget.

*__श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र):__ मैं राजकुमार सैनी प्रथम बार इस सदन में लोक सभा क्षेत्र कुरूक्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मुझे बजट चर्चा मे ंसम्मिलित होने का मौका मिला इसके लिए मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

दूसरा धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का करता हूँ जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत के प्रजातंत्र को गौरवपूर्ण दृष्टि से देखा व सराहा गया।

तीसरा धन्यवाद मैं धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र की जनता का करना चाहूँगा, जिस धरती से मैं चुनकर आया हुं, जहां प्राचीनकाल में महाभारत का युद्ध हुआ और अन्याय पर न्याय की जीत हुई। आज फिर वहां के लोगों ने देश के इतने बड़े उद्योगपति, पूंजीपति व कोयला चोर के खिलाफ मुझे जिताया मैं कुरूक्षेत्र की जनता को शत् शत् नमन करता हूँ।

इंसान को जिंदा रहने हेतु रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। अच्छे जीवन-यापन हेतु बिजली, पानी, सड़क की जरूरत है। अच्छे बौद्धिक विकास हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है और सुरक्षा और शांति से जीने हेतु आंतरिक व बाहरी सुरक्षा की जरूरत है। हमारे वित मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बहुमुंखी विकास करने व रोज़गार के साधन जुटाने वाला बजट पेश किया है। जिसमें हर वर्ग से जुड़ी हर समस्या का समाधान है।

मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 50 प्रतिशत जनता की आजीविका कृषि पर आधारित है। जिस पर वित्त मंत्री जी ने 1000 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया और हरियाणा और तेलंगाना में 200 करोड़ रूपए कृषि उद्यान के लिए प्रावधान कर यह साबित कर दिया है कि यह सरकार लोगों को काम के मौके देकर कमा कर खाने की पक्षधर है।

इंसान को तन ढँकने के लिए सस्ते अच्छे कपड़े की पूर्ति हेतु हमारे वित मंत्री जी ने 6 बड़े वस्त्र मेगा क्लस्टर स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान कर अपनी मंशा दर्शाई है कि वह हर क्षेत्र की पूर्ति के साथ-साथ रोज़गार भी उत्पन्न करें। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

आज हमारे शहरों में मकान खरीदना, बनाना आम आदमी की पहुंच से परे हैं। जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 बड़े शहरों के निर्माण हेतु उन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जिन्हें अच्छा व सस्ता घर चाहिये 7060 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वित वर्ष में रखा है और 4000 करोड़ रूपए अलग से इस वित वर्ष के लिए प्रस्तावित हैं। इस स्कीम में 2022 तक हर व्यक्ति का अपना घर होगा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि यह सरकार कितनी दूरदृष्टि रखती है परंतु यहां पर यह कहने से भी मैं संकोच नहीं करूँगा कि इस बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए चीन की तरह कोई ठोस कानून नहीं लाया जायेगा तब तक हम इस समस्या को सुलझा नहीं पायेंगे।

मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूँ कि जिस पुकार से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन दूरगामी क्षेत्रों में विकास को गति मिली थी। पिछली सरकार ने इस ओर 10 प्रतिशत भी काम न करके उन लोगों को तो हताश-निराश किया ही है, परंतु वहां से फल-सब्जियां इत्यादि जो उपलब्ध हो सकती थी, जिससे कि बाज़ार भाव संतुलित हो सकता था, उससे देश महरूम रहा और विकास ठप हुआ। आज इस सरकार ने पुनः इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 14000 करोड़ रूपये का प्रावधान सड़कों के लिए और दूर-दराज़ के क्षेत्रों के विकास और आवास के लिए 8000 करोड़ रूपए का प्रावधान कर अपनी गंभीरता जताई है। जहां मैं बजट का समर्थन करता हूँ वही वित मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ।

आज़ादी के 67 वर्ष के पश्चात् भी देश स्वच्छ पानी से वंचित है। यह भला किसका कसूर है। यह कसूर उनका है, जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक राज किया हो, परंतु यह सरकार कटिबद्ध है 20000 बसावटों पर 3600 करोड़ रूपये खर्च कर हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम करेगी।

दुनिया के किसी भी देश की तरक्की और विकास का आंकलन अगर होता है तो उस देश की बिजली आपूर्ति से आंका जाता है। मुझसे एक बार जर्मनी दौरे में एक जेपनीज ने पूछा कि आपके देश में बिजली कितने घण्टे मिलती है तो मेंने कहा एवरेज 8 घण्टे तो उसका जबाव था कि आपका देश दुनिया की दौड़ में हर रोज़ 16 घण्टे पीछे रह जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-

क. आज हमें सुदूर क्षेत्रों से थर्मल प्लांट तक कोयला ढुलाई के लिए रेलवे का अत्यधिक इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके विपरीत इस सारे खर्च को बचाने के लिए हम थर्मल प्लांट कोयला खदानों के पास लगाए और बिजली का ट्रांसमिशन पूरे देश में करें।

ख. हमारे पास दुनया भर का पानी फ्री में हिमाचल/उत्तरखण्ड/जम्मू कश्मीर और अन्य पर्वतीय राज्यों से समुद्र में जा रहा है। हम पूरे बजट को समेट कर सबसे पहले बजट का एक बड़े हिस्से से एक-एक किलोमीटर की दूरी पर बिजली घर बनाकर बिजली पैदा करना चाहते हैं, जहां से असंख्य लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए वित मंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घण्टे 7 दिन बिजली आपूर्ति हेतु 500 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान कर एक आशा की किरण जगाई है।

आज शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकारी स्कूलों व अस्पतालों की बजाए आज प्राइवेट स्कूल और अस्पताल पर जनता का ज्यादा विश्वास स्थानांतरित हो चुका है। इसका मूल कारण पिछली सरकारों ने तन्ख्वाहे तो दी पर सेवाओं की बजाए हड़तालों और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। यदि कोई पूछने वाला होता तो देश का ये हाल न होता। अभी तक लाख रूपये पाने वाला कर्मचारी हड़ताल कर देता है, परंतु 10000 रूपये प्राइवेट सेक्टर में तन्ख्वाह पाने वाला 12 घण्टे काम करने के पश्चात् भी उफ तक नहीं करता। हम प्राईवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की विषमता को नज़दीक लाए। हमारे वित्त मंत्री जी ने जहां एक और एम्स तथा शिक्षण संस्थान खोलने के लिए बजट में प्रावधान रखा है वहीं दूसरी और भ्रष्टाचार रोकने और क्वालिटी सेवाएं प्राप्त करने के लिए चैक व निरीक्षण का भी प्रावधान किया है।

ई-वीजा के माध्यम से जहां बड़े-बड़े हवाई अड्डे बनाकर पर्यटन के माध्यम से रोज़गार देने का प्रावधान है। वहीं हमारे देशा की संस्कृति व सभ्यता की पहचान कुरूभूमि कुरूक्षेत्र जहां पर प्राचीनकाल में महाभारत का युद्ध हुआ था व जहां पर प्राचीन विलुप्त हुई सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए इसे भारत के मानचित्र पर एक विशेष पर्यटन स्थल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने 3 अप्रैल, 2014 को विजय दिवस रैली के दौरान यहां पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने व रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की घोषणा की थी व इसके साथ-साथ कुरूक्षेत्र से यमुनानगर तक नई रेलवे लाईन भी आवश्यक है। इन सभी कार्यों के लिए वित्त मंत्री जी ने इस बजट में लगभग 4000 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

अंत में, मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूँ कि जहां पर 40 दिन में महंगाई रोकने पर चर्चा हुई, वहां पर कपड़ा जो 30 रूपये मीटर था वह 300 रूपये मीटर बिक जाए तो चर्चा नहीं होती। दवाई किस भाव बिके चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती है तो आलू, टमाटर और प्याज पर।

यह सरकार सब्जियों के प्रति हर रोज़ के ऊँचे-नीचे भावों के कारण कभी आलू गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं और कभी टमाटर सड़को पर फेंके जाते है। इस समस्या को भंडारणो व कोल्ड स्टोरों के माध्यम से हरी सब्जियों के दाम फसल कम-ज्यादा होने से भाव प्रभावित न हो, इसके लिए 5000 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वित वर्ष में कर इस सरकार ने अपनी गंभीरता का परिचय दिया है। इसलिए मैं इस प्रगतिशील बजट का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ।

*__श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर)-__ माननीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी द्वारा पेश किये गये बजट 2014-15 का समर्थन करता हूँ।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया पहला बजट देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। देश का विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक बाध्यता होते हुए भी जनाभिमुख बजट देकर चुनावी वायदों की पूर्ति करने की आकांक्षा जगाने वाला और सभी क्षेत्रों को आश्वस्त करने वाला बजट देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।

पिछले कई वर्षों से मध्यम वर्ग तथा नौकरीपेशा लोगों की व्यक्तिगत आयकर मुक्त सीमा में बढ़ोतरी करने की अपेक्षा पूर्ण हो गई है। आयकर मुक्त सीमा दो लाख 2.5 लाख तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख करने से उन्हें राहत मिलेगी। इसी तरह गृह ऋण कटौती सीमा 1.5 से 2.00 लाख करने से भारी बचत होगी। भविष्य निर्वाह निधि में निवेश की सीमा एक लाख से डेढ़ लाख करने से भी फायदा होगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही है। बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए नाबार्ड के द्वारा 25 हज़ार करोड़ रूपये के आवंटन में 5 हज़ार करोड़ रूपये की बढ़ोतरी, किसानों के सुरक्षित भंडारण हेतु 5000 करोड़ रूपये की राशि किसानों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रशिक्षण, जानकारी हेतु किसान टी.वी., ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना, मनरेगा को कृषि से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्धता के लिए आवास बैंक, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 8 लाख करोड़ रूपये की भारी धनराशि, जल संवर्द्धन के लिए नया निरंचल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा कृषि तथा किसानों को विकास के बड़े अवसर सुलभ कराये गये हैं।

मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश में नये चार एम्स की घोषणा में विदर्भ में भी एक एम्स देने की घोषणा की है। इससे विदर्भ में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेंगी। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा को कारगर कराने के लिए 12 नये मेडिकल कॉलेज भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस सरकार ने देश के ग्रामीण तथा छोटे शहरों में बेरोज़गारी कम करने के लिए और कौशल विकास के लिए परंपरागत व्यवसायी, जिन्हें हम बारा बलूतेदार भी कहते हैं। ऐसे कुम्हार, चर्मकार, लौहार, सुनार, बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी आदि के रोज़गार संवर्द्धन एवं अत्याधुनिकरण के लिए 10,000 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं। यह नया प्रयास देश में बेरोज़गारी खत्म करने में सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

बजट में सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान देने को कोशिश की गई, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के संविदा कामगार जिसे हम कान्ट्रेक्ट लेबर कहते हैं, उनकी सुरक्षा तथा हित रक्षण के लिए कान्ट्रेक्ट लेबर एबोलिएशन एक्ट 1970 में उचित संशोधन कर उन्हें राहत देने की पहल सरकार को करने का मैं आग्रह करता हूं। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विशेषकर कोल इंडिया, सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में बड़े पैमाने पर कामगारो की कटौती की जा रही है, इससे बेरोज़गारी को बढ़ावा मिल सकता है। इस पर ध्यान देकर कामगार कटौती न हो, इसके लिए भी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा पी.आर.एस. के नाम पर स्वयं ही भारी भत्तों का निर्धारण करने से इन सार्वजनिक उपक्रमों की अप्रत्यक्ष लूट हो रही है। वेतन के अतिरिक्त मनमाने भत्तों के कारण पी.एस.यू. की आर्थिक हानि की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस पर लगाम लगाने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की घोषणा का स्वागत करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। देश में सिंचाई की विषमता खत्म करने के लिए सिंचाई पर किसानों का अधिकार होने के लिए इसे कानून में परिवर्तित करना चाहिये। इससे किसानों को सुनिश्चित लाभ हो सकता है। सरकार इस पर अवश्य विचार करें।

देश में सरकार द्वारा किसान आत्महत्या प्रवण जिलों को चिन्हित किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का यवतमाल जिला उसी श्रेणी में आता है। इसलिए यवतमाल जिले के साथ विदर्भ के किसानों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस क्षेत्र के दाभोड़ी गांव में स्वयं दौरा कर स्थिति की भयावहता देखी है। इसलिए यहां पर सिंचाई, बिजली, सड़क, कृषि उत्पाद खरीद केन्द्र, प्रत्येक परिवारों को मकान, दूध, बकरी और कुक्कुटपालन जैसे स्वरोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि बजट में इसका ध्यान रखा जायेगा।

आजकल रियल इस्टेट में निवेश काफी बढ़ गया है, धनवान लोग ग्रामीण तथा छोटे शहरों में भूमि खरीद कर इस्टेट निवेश के तौर पर रखने के कारण भारी भूमि खाली पड़ी है, इसका संज्ञान लेकर अप्रयुक्त भूमि को वापस लेकर भूमिहीन किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए1 पिछली सरकार के कार्यकाल में 1 लाख 86 हज़ार करोड़ रूपये का कोल घोटाला उज़ागर हुआ। अनियमित आवंटन के कारण राजस्व के भारी नुकसान को देखते हुए आवंटित सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन तत्काल रद्द कर इसे नीलामी, बोली के द्वारा तथा कोल इंडिया को कोल उत्खनन के लिए देने का निर्णय सरकार को लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

कोल क्षेत्र में अवैध खनन का प्रचलन बढ़ रहा है तथा कोल की कमी तथा आपूर्ति में कठिनाई को देखते हुए कोयले को पुनः जीवनावश्यक कानून (ई.सी. एक्ट) में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। देश में बिजली उत्पादन संयंत्रों के द्वारा क्षमता से कम बिजली निर्माण करने से बिजली की कमी हो रही है। बिजली उत्पादन संयंत्रों का प्रबंधन कड़ा करे तथा सरकार इन बिजली उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता का कम से कम 90 फीसदी उत्पादन अनिवार्य करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें या कानूनी बाध्यता बनाने के लिए उचित कदम उठाये।

विदर्भ में किसान कपास का भारी उत्पादन करते है, लेकिन वहां पर कपास प्रसंस्करण इकाईयां बहुत कम है। इससे किसानों को उचित दाम तथा रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए विदर्भ के पास उत्पादक क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। वन बहुल क्षेत्रों में वनों की अधिकता के कारण यहां पर विकास की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी तकलीफ होती है। परियोजनाओं के वर्षों से लंबित रहने के कारण उनका लागत मूल्य ही बढ़ता है, इसलिए पुराने वन संबंधी कानूनों को कालसंगत तथा वन क्षेत्रों में रहने वालों को हितकारी बनाया जाना चाहिए। इसलिए सरकार से वन संवर्द्धन कानून 1980 तथा 1927 में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। इसी तरह पर्यावरण प्रदूषण पर नई गाइडलाईन बनाने के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। पर्यावरण का संतुलन कायम रखने के लिए अब प्रदूषणमुक्त ऊर्जा की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए सोलर, पवन तथा हाइड्रो ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार इसे प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को भी दिशा-निर्देश जारी करें।

सरकार ने बजट पेश करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, अंतरिक्ष, सरक्षण, संशोधन तथा नये प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए सार्थक पहल की है। देश के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखकर किये गये विभिन्न प्रावधानों से बजट का दूरगामी असर होगा। बजट में किये गये प्रावधानों में लोगों को राहत मिलने से देश एक नये विकास के पथ पर सतत अग्रसर रहेगा,यह विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं बजट का समर्थन कर वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देकर उनका अभिनंदन करता हूं।

*SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): I represent a rural parliamentary constituency, namely Aska of the state of Odisha. On behalf of the people of the state of Odisha in general and people of the Aska Parliamentary constituency in particular, I would like to draw the attention of the Honourable Finance Minister on the following few concerns.

Odisha has been demanding for the review of royalty on minerals, which was due since last couple of years. In the Budget Speech, an assurance was given by the Finance Minister to this august House that the royalty on minerals will be reviewed soon. This is certainly a welcome step. The revision of the royalty on minerals would certainly benefit the mineral rich states and I am sure that Odisha will get its due share.

The proposal of linking rivers is also a welcome step and I would like to draw the attention of the Minister to consider the proposal of linking two rivers i.e. Bansadhara and Rushikulya for the larger benefit of the people of Odisha in general and farmers of my parliamentary constituency. This

proposed river linking project will be a win-win situation. It will help farmers of the Ganjam District, a southern district of the state of Odisha, with adequate water for irrigation and grow cereals and horticulture crops. Given the vagaries of nature, assured irrigation for cultivation will be an added advantage for the farmers, which will not only address the concern of migration but also enhance the income of the farming community with a sustained base for their livelihood.

You might be aware that flood in Bansadhara has been a common feature every year in Gajapati district. Since there is no permanent flood control provision in Bansadhara, the people in the riverside villages of Bansadhara always live in fear when rainy season comes. If these two rivers are linked, water can easily be diverted to Rushikulya and stored for irrigation during the summer. This will also address the concern of drinking water crisis in major towns of Ganjam district. This is to inform you that acquiring land for said purpose will not be an issue.

Further, I would like to congratulate the announcement of the construction of 8500 km of National Highway in the current financial year by the Finance Minister.

There is an urgent need for renovating two existing irrigation projects, which have been there since pre-Independence period, namely Bhanjanagar and Rushikulya Medium Irrigation project and are in my parliamentary constituency. For this, appropriate budgetary provisions for de-silting may be considered. Further, once the proposed river linking is worked out, water can be stored in these two irrigation projects.

Honourable Finance Minister in his budget speech mentioned that there is a need to provide assured irrigation to mitigate risk. To improve access to irrigation the proposal to initiate the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, with a sum of Rs. 1000 crore, is definitely a welcome step. However, the resource requirement would be much more than what was proposed in the budget 2014-15, looking at our agro-climatic conditions and dependence of the farming community of dryland / rainfed agriculture.

In this regard, I would like to take this opportunity to share my concern to take up and renovate the existing medium irrigation project in my constituency, namely Dhanai irrigation project. The catchment area of the said project is yet to be utilized. Hence, by raising the embankment, adequate water can be stored and can be used for irrigation purposes. Grants from Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana may kindly be considered for this purpose.

As you would be knowing that my constituency is linked with NH-16 (Kolkatta to Chennai) NH-59 (Gopalpur to Raipur) and NH –157 which connects Aska to Bhanjanagar, a stretch of about 55 k m i.e. from Keshpur (on NH-16) to Aska (on NH –157) may be considered for converting the existing State Highway to National Highway. This proposed connectivity will help saving time and energy while creating a number of avenues of livelihood options for the people of my constituency.

At the end, I would like to request to address the problems of Odisha, which is one of the backward and poorest states of the country, by fulfilling the longstanding demand that is Special State status to Odisha with a view to spur growth and prosperity.

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGLUR): The budget 2014-15 presented by the Finance Minister has successfully captured the imagination of the people, recognizes the aspirations of a new India which is looking towards the Government for decisively moving towards high growth, low inflation and more jobs. In a clear move to achieve fiscal consolidation and economic recovery, the Budget has made many concrete announcements. Schemes like 'Skill India' will boost the confidence of India's youth and create massive job opportunities in the country.

I thank the Prime Minister and Finance Minister for giving a very high priority to agriculture. The budget puts into action the Prime Minister's commitment and vision to make villages and farmers strong through schemes for agricultural growth, irrigation and connectivity.

The commitment shown in the budget to usher in technology-driven Second green revolution with focus on higher productivity and protein resolution. Another major area in focus would be promoting organic farming in the North-Eastern region of the country where there is immense potential for this. The provision of soil health card to all the farmers is a path-breaking initiative and it will help farmers reap better harvests with lesser investment on inputs.

The 'Pradhan Mantri Gram Sinchyee Yojana' designed to provide irrigation facilities in rain fed areas will not only benefit the farmers but also strengthen our food security.

Union Government has proposed to launch a pan India Programme called "Digital India" to further bridge the divide between digital "haves" and "have-nots". This would ensure Broadband connectivity at village level, improved access to services through IT enabled platforms, greater transparency in Government processes and increased indigenous production of IT hardware and software for exports and improved domestic availability.

The Government has also proposed to set-up a National Rural Intranet and Technology Mission for services in villages and schools, training in IT skills and E-Kranti for government service delivery and governance scheme.

The Budget has also proposed to hike the income tax exemption limit from existing Rs. 2 lakhs to Rs. 2.5 lakhs which will provide much needed relief to salaried class.

I also thank the Finance Minister for extra allocation to support pensioner keeping in view that the number of pensioners in the country is now more than the number of serving officials.

The budget has also allocated funds to Ganga rejuvenation and river interlinking project which is indeed a welcome step.

I am elated at the announcements to encourage new and renewable energy. (solar, wind) and development of transmission and distribution. This will go a long way in ensuring 24x7 power to all. I also welcome steps for incentivizing solar powered water pumps, and setting up of solar parks and moves for setting up solar plants on banks of canals.

The Union Budget 2014 has many aspects which would promote education in the country.

- The focus of the Budget has been on education and skill development. In particular, the Plan Budget of Higher Education has been considerably increased in 2014-15. In the School Education and Literacy sector also, the increase has been substantial.
- The Budget has specially focused on education of girl child which is one of the major priorities of this Government.
- The Budget highlights the resolve to provide the residual one lakh girls toilets and drinking water facilities in schools which will benefit 100 lakh girls in the First phase. This would enable girls to not only enroll in schools but also stay in schools. When girls get the needed sanitation facilities in schools, they would demand similar facilities at home, leading to a cleaner India.
- The "Beti Bachao Beti Padhao Scheme" would not only improve the adverse sex ratio but also ensure that girls are educated.
- Setting up virtual classrooms and Massive Open Online Courses are planned. A national e-library will also be created which will be repository for all educational resources.

India has emerged as one of the largest PPP markets in the world with over 900 projects in various stages of development in road and highways sector. Furthermore, proposals worth Rs. 37,880 crores have been made in the budget, to be invested in National Highways development as well as that of State roads.

I further hail several budget proposals which will accelerate the integrated development of rural areas. An important initiative in the budget, 'Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission' will provide, preferably through PPP mode, better civic infrastructure and associate services for the people living in rural areas. This will include development of economic activities and skill development. In power sector, 'Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana'

will be launched to augment power supply in rural areas and strengthen transmission and distribution systems. "Swatchh Bharat Abhiyan" has been proposed in the budget to achieve total sanitation by the year 2019.

The Budget recognizes the core strengths of the textiles sector and aims to promote them with a strong human emphasis. The textile industry, which plays a pivotal role in the economic life of India, also majorly contributes to industrial output, employment generation and the export earnings of the country. The textile sector is the Second largest provider of employment after agriculture. By proposing Six new "Textile Clusters", the Budget gives boost to Indian textile industries and also create job opportunities.

The Government has allocated Rs. 1.15 lakh crore for food subsidy in 2014-15 Budget to ensure wheat and rice at reasonable prices to weaker sections of the society. It includes a provision of Rs. 88,500 crore for implementation of National Food Security Act.

The welfare of tribal girls and student welfare is one of the focus areas of the budget for 2014-15. Educational assistance to scheduled tribe children has also given high priority it includes assistance for study tour to school and college going students, supply of study material to all students studying in high school, higher secondary school and colleges and assistance to provide laptop to ST students studying professional courses in approved University/Institutes.

Acknowledging the importance of urban development and urban renewal to meet the growing aspirations of the people for better urban living, the Union Government has increased Plan Outlay for urban related projects by 251.44% in the Budget. To meet the demands of better urban living from growing urbanization, besides increasing Plan Outlay, the Government has offered tax and non-tax incentives to promote investments in urban infrastructure and housing sectors.

This is a transformative budget focusing on policy initiatives and a heavy emphasis has been laid on investment-led growth. The budget addresses immediate concerns of all section of the society - – young, old, poor, women, workers, farmers, SCs/STs, backward sections of the society, middle class, entrepreneurs and even people with disabilities. I congratulate the Union Finance Minister for delivering this growth-oriented, pragmatic budget. The Finance Minister has taken several strong steps for the revival, rejuvenation and resurgence of the Indian economy and presented a tangible and actionable roadmap to lift crores of people out of poverty. The thrust on skill development, manufacturing, education, clean and renewable energy, infrastructure and healthcare, are particularly heartening to see.

I completely endorse the Union Budget as a visionary step towards fulfilling the aspirations of all Indians: "Sabka Saath Sabka Vikas". With these words, I support the Budget.

*SHRI RAMCHANDRA HANSDAH (MAYURBHANJ): The Finance Minister has not been able to do any magical stunt in presenting the Union Budget for 2014-15. He is simply following heels of the Congress led UPA Government by not being able to do away with the not so desirable fiscal parameters and seems to have wavered from the path of fiscal consolidation as envisaged by the FRBM Act. The claimed GDP growth rate of 13.4% is quite illusory considering the present high rate of inflation. Increase in FDI cap to 49% vis-Ã -vis disinvestment to the tune of Rs 48,425 crore will only reduce the national worth of the PSUs and consequential subjugation of these companies to financial imperialism. Though there is a provision of bank capitalization infusing Rs 2,40,000 crore by 2018, the intention of the Government is skewed to the disadvantage of the farmers and the marginalized section of the society. Had we dispensed with 'Statute of Unity' with budgetary support of Rs 200 crore – we could have provided 28,572 poors decent houses to live in.

The Budget casts gloomy picture in addressing the regional disparities existing among the States-where long term package of special central assistance could have been extended to bring the States lagging behind in developmental parameters at par with others. Even the fund flow under Tribal Sub-Plan (TSP) and Special Component Plan (SCP) in various ministries is hazy. Compulsion of proportionate fund allocation could have been enforced if a separate central statue in this regard had been framed.

Also 147 Centrally Sponsored Schemes (CSPs) existing earlier have been reduced to 66. But it is a fact that most of the time States are not able to garner the CSPs for lack of priorities given by the States or for similar such schemes being implemented by the States. The equitable flow of fund could have been ensured if instead the States are given in terms of block grants to invest in the CSPs of their choice. This proposal coming from various quarters may be given serious thought.

My State Odisha is among ones which are endowed with rich minerals. My State was losing vast revenue as there was no mandatory review of royalty change in minerals since 2009. I welcome the statement by the Finance Minister for the promise to make a review soon. Implementation of GST will also ensure tax related liberalization to the States.

*श्री चाँद नाथ (अलवर)- भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोज़गारी तथा सीमित समय में जो एक संतुलित बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह बहुत प्रशंसनीय है। मैं ई.पी.एफ. (इम्पलाईज प्रोविडेंट फंड) के सभी अभिदाता सदस्यों की ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। जिनके लिए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन 1000/- रूपये कर दी है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक ई.पी.एफ. स्कीम के अंतर्गत पेंशन लेने वाला पेंशन बताते हुए शर्मसार हो जाता था, क्योंकि कई व्यक्तियों की पेंशन 200/- रूपये से भी कम थी। मेरा सुझाव है कि न्यूनतम पेंशन 1500/- रूपये कर दी जाए, और यह बढ़ोतरी वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित निवेशों में से जो कि दावारहित धनराशि रह जाती है, का प्रयोग बढ़ी हुई पेंशन के लिए किया जा सकता है।

लोगों की बढ़ती संख्या तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन की बढ़ती हुई गति देखकर स्मार्ट शहर की योजना का स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है कि कुछ शहरों का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने के बारे में कुछ ऐसे शहर चुने जायें जो कि ऐतिहासिक होने के साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक हों, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसा एक शहर मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में तिजारा है। तिजारा शहर जैन समुदाय, जो कि अल्पसंख्यक है, का एक धर्मस्थल है। मेरा सुझाव है कि चालू वित्त वर्ष में इसको स्मार्ट शहर की तरह विकसित किया जाए। इससे यह शहर संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास और रोज़गार सृजन के लिए विकसित हो।

प्रारंभिक शिक्षा को मुख्य प्राथमिकता प्रदान कर सभी विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास बहुत आवश्यक है, परंतु केवल 10 प्रतिशत स्कूल शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी बहुत कम है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के विकास के लिए स्कूल मूल्यांकन प्रोग्राम बहुत आवश्यक है ताकि युवा लीडरशीप तथा कौशल का विकास हो सके। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण प्रोग्राम का स्वागत करता हूं तथा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाये तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना ऊँचा कर दिया जाये कि माता-पिता बच्चो को प्राईवेट स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में भूल जाये।

मैं कृषि में वृद्धि बनाये रखने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों द्वारा की जारी आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण बैंकों से लिए जाने वाले ऋण का समय पर भुगतान न होना है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ रूपए का लक्ष्य रखा गया है। यह ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाना है। जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज किसानों को देना पड़ता है बाकी सरकार सब्सिडी के रूप में उन किसानों को देती है, जो भुगतान के समय पर कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि यह ब्याज 6 प्रतिशत कर दिया जाये या सब्सिडी 3 से 4 प्रतिशत कर दी जाए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि किसानों को अपने बाज़ार विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया जाये, जो कि किसानों को किसान बाज़ार विकसित करने के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता दे तथा किसानों के अर्जन क्षमता के लिए भण्डारागार क्षमता का अभाव न हो।

राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी सास संस्थाएं राज्य में मनरेगा श्रमिकों को बैंक के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संस्थाओं द्वारा 34 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक रूप से हो रहा है, परंतु इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हानि हो रही है, जिससे इनकी लाभप्रदता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति हेतु अनुमानित रूप से राशि उपलब्ध करवाई जाये। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सहकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि आदानों पर अनुदान का वितरण, छोटे तथा सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। मनरेगा अधिनियम में प्रावधान होने के कारण मनरेगा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जा रही है, किंतु अल्पकालीन सहकारी सास संस्थाओं की भूमिका को देखते हुए मनरेगा राशि राज्य के सहकारी बैंक में रखी जानी चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य व जिला स्तर पर चार तरह की निधियाँ गठित करने की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 में भी राज्य आपदा प्रतिसाद निधि तथा जिला आपदा प्रतिसाद निधि और राज्य आपदा शमन निधि और जिला आपदा शमन निधि के गठन किये जाने का प्रावधान है।

मैं केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में न केवल राज्य व जिला स्तर पर उपरोक्त निधियों का गठन करें, बल्कि इन निधियों में राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) की तरह 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का निश्चित किया जाये।

*SHRI C. GOPALKRISHNAN (NILGIRIS): I support the Union Budget 2014-15 presented by the Hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley.

Our dynamic revolutionary leader 'Amma' has welcomed the General Budget for the year 2014-15. Following the footsteps of our leader, 'Amma', I also welcome and support this General Budget.

I want to say that it is a growth-oriented budget and lays stress on infrastructure, urban development, rural development, ports among others. The allotment of Rs. 7,060 crores for Smart cities along with giving some concessions to tax payers is a right decision for growth of the country.

I also thank the Finance Minister for providing Rs. 100 crore for modernization of madarasas which is higher than what the previous UPA Government has provided.

I thank the Finance Minister for providing a small tax benefit by raising slabs. The Finance Minister has announced that Personal Income-tax exemption limit raised by Rs. 50,000 that is, from 'Rs. 2 lakh to Rs. 2.5 lakh in the case of individual taxpayers, below the age of 60 years,

Exemption limit raised from Rs. 2.5 lakh to Rs. 3 lakh in the case of senior citizens.

I am sure the Finance Minister will address the fiscal deficit. Some people say it is big. But a good portion of it is interest costs and subsidies. Subsidies are not changing right now. The question is how we can reduce subsidies and how unproductive they are. The Finance Minister has promised that they will fix things by more focused food and fuel subsidy. I welcome this decision.

Regarding MGNREGA issue, the money will be spent but for "more productive asset creating and linked to agriculture. I welcome it.

The Finance Minister has also promised single-window-customs clearance, which should ease regulatory pains for importers. I also welcome the initiative of the Finance Minister for a better tax assessment, including advance rulings and defined committees for settlement.

I welcome the initiative of the Finance Minister to spend Rs. 500 crore for giving training to the elementary school teachers. To set up five IITs and five IIMs the allocation is Rs. 500 crore. I want the Finance Minister to set up an IIM in Tamil Nadu also.

In my Nilgiris constituency, Hindustan Photo Film is an Indian-based public sector manufacturer of photographic films, cine films, X-ray films, graphic arts films, photographic paper, and chemistry. It is based out of Udhagamandalam, a hill station in Tamil Nadu. Their photographic films are sold under the name "Indu", which means "silver" in Sanskrit (silver halides are used in film). Hindustan Photo Films Ltd., which employed over 714 employees as on March 31, 2012, was declared sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction in 1996. In the month of March 2013, a Rs. 181 crore VRS package for employees of the ailing PSU Hindustan Photo Films based on notional pay scales of 2007. I request the Finance Minister to take necessary action to revamp it for proper functioning.

The NH 67 from Mettupalayam-Conoor-Ooty-Gudalur approximately 90 kms is very badly damaged and it is very difficult to travel on this road. Ooty is the international tourist place in my constituency. So necessary fund may be allotted to repair the road.

Reliah Dam in Coonoor is the main source for drinking water to the people of Coonoor Municipality. The capacity of the dam was very low when compared to the present population. So the capacity of dam needs to be expanded as much as possible. Considering the present population, I urge upon the Government to take necessary steps to allocate necessary funds to increase the capacity of the dam.

The Nilgiri is also very familiar for the Floriculture Green Farm. This Floriculture Farms are suffering due to heavy drought and heavy landslides. They are incurring heavy losses and some of the Farms were closed. To save this Green Farms, I urge upon the Government to introduce exclusive insurance scheme and loan waiving scheme.

With these words, I support the General Budget, 2014.

*__डॉ. यशवंत सिंह (नगीना)-__ आज मैं वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सराहे जा रहे इस बजट का मैं भी समर्थन करता हूं।

जब ये देश आज़ाद हुआ था,इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने यह आशा की थी कि इस देश में अगर वोट का अधिकार बराबर का है तो देश की प्रगति में भी बराबरी का अधिकार मिलेग, परंतु खेद के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। इस देश के दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा मिला। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कोई सरकार किस लिए होती है, सरकार का क्या दायित्व होता है, यह शायद सभी को मालूम है। हम सब जानते हैं कि एक गरीब व्यक्ति सरकार से मदद चाहता है तथा उम्मीद करता है कि उसके बुरे दिनों में सरकार उसकी मदद करेगी तथा उसकी गरीबी के स्तर में सुधार करके उसे इस लायक बनायेगी कि वह गरीबी के अभिशाप से ऊपर उठ सके। उसी के साथ एक अमीर व्यक्ति अपनी कमाई को कई गुणा बढ़ाकर कम से कम टैक्स सरकार को देना चाहता है। अगर गरीब को कुछ मिलता है तो वह सरकार का गुणगान करता है, परंतु अगर अमीर को आशा से ज्यादा भी मिले तो भी सरकार की निंदा करता है।

सरकार की नीति अभी तक गरीबी को कम करने की रही है, परंतु गरीबी का विनाश करने की नहीं रही। हम सबको समझना चाहिये कि दो का दुगना चार होता है तथा सौ का दुगना दो सौ होता है, इसलिए गरीब और अमीर दोनों की आमदनी दुगना करने पर आमदनी तो दो गुना हो जाती है, परंतु दोनों का अंतर 98 से बढ़कर 196 हो जाता है, जैसा आज तक होता आया है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, जिनसे इस राष्ट्र को बहुत उम्मीद है और उनके द्वारा यह बात कही गयी थी कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है एवं गरीबी खत्म करने के लिए सरकार है। इसमें गरीबी खत्म करने वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इस बजट से ऐसा कोई बड़ा चमत्कार होता दिखाई नहीं दे रहा है।

अगर गरीबों के बारे में सोचा जाए तो सरकार के द्वारा गरीबों के बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों के सुधार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज बच्चा विद्यालय जाता तो जरूर है, परंतु शिक्षकों की कमी तथा खराब प्रबंधन के कारण बिना पढ़े वापस आ जाता है तथा पढ़े या न पढ़े अगली कक्षा में प्रमोट हो जाता है। उस बच्चे से देश का कोई भी नागरिक यह अपेक्षा नहीं करता है कि यह बच्चा देश के विकास में सहायक होगा, भले ही वह इन बुरे हालात के विद्यालयों से पढ़कर भी परम आदरणीय श्री ए.पी.जे.अब्दुल कलाम जैसा महान सांइटिस्ट एवं राजनेता क्यों न बन जाये।

जब देश का बंटवारा हुआ था तो जो हमारे साथी पाकिस्तान से वापस आये थे, उन्हें सरकार द्वारा जगह-जगह पर बाज़ारों में दुकानें, जमीनों का आवंटन आदि करके उनको मुख्य धारा में लाया गया था। सरकार से समुचित ध्यान से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और वे सभी देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग करके देश की प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आज सरकार को जरूरत है कि कम से कम दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समाज के गरीब व्यक्तियों को अभियान चलाकर मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास करें। इस बजट में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 200 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है, जो ऊँट के मुंह में जीरा है। मेरा मानना है कि जो धनराशि एस.सी./एस.टी. एवं गरीबों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाती है और जिसका परिणाम आज तक जीरो दिखाई देता है, इस पूरी धनराशि को गरीबों को मकान बनाने, व्यवसाय करने हेतु तथा उनके बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु उपयोग करने का मौका दिया जाये तो करोड़ों लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है।

इस देश का किसान बढ़ती महंगाई तथा बढ़ते परिवार के कारण परेशान है। इसमें मुख्य तौर पर गन्ना उत्पाद करने वाले किसान का बुरा हाल है। किसान लागत लगा कर गन्ना उत्पादन करता है तथा शुगर मिल में गन्ना जाने के बाद सालों साल भुगतान नहीं हो पाता। यह कैसा न्याय है। मेरे क्षेत्र में बजाज ग्रुप की बिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों का भुगतान नहीं होने से वहां पर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तथा मिल मालिक एवं प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसान अपनी फसल डालने के बाद भी पैसे-पैसे को मोहताज हैं। बजट में गन्ने के किसानों के भुगतान हेतु इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था हेतु प्रावधान की आवश्यकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी ओर इस बजट में अच्छी सोच रखी गई है। बस मेरे द्वारा सुझायी गयी बातों को सम्मिलित किया जाये। मैं अपनी ओर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

*__SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE):__ I support the Union Budget 2014-15 presented on 10.07.2014 by the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley.

Our Tamil Nadu Chief Minister 'Amma' has appreciated the Maiden General Budget for the year 2014-15 presented by the Hon'ble Minister and I am also welcoming and supporting this budget.

It is a growth-oriented and lays stress on infrastructure, urban development, rural development ports among others. The allotment of Rs. 7,060 crores for Smart Cities along with giving some concessions to tax payers is a right decision for the growth of the country.

I thank the Finance Minister for providing a small tax benefit by raising slabs. The Finance Minister has announced that Personal Income-tax exemption limit raised by Rs. 50,000 that is, from Rs. 2 lakh to Rs. 2.5 lakh in the case of individual taxpayers, below the age of 60 years,

The Finance Minister has promised that they will fix things by more focused food and fuel subsidy. I welcome this decision.

I welcome the promise given the Finance Minister that he will fix food inflation by reforming the FCI and the Public Distribution System. The monsoon is 43 percent below normal right now. I am sure he will be able to do it.

The Finance Minister has also promised single-window-customs clearance, which should ease regulatory pains for importers.

I thank the Finance Minister for providing a small tax benefit by raising slabs. Exemption limit raised from Rs. 2.5 lakh to Rs. 3 lakh in the case of senior citizens.

I also thank the Finance Minister for providing Rs. 100 crore for modernisation of madarasas which is higher than what the previous UPA Government has provided.

I am sure the Finance Minister will address the fiscal deficit. Some people say it is big. But a good portion of it is interest costs and subsidies. Subsidies are not changing right now. The question is how we can reduce subsidies and how unproductive they are. The Finance Minister has promised that they will fix things by more focused food and fuel subsidy. I welcome this decision. I welcome the initiative of the Finance Minister to spend Rs. 500 crore for giving training to the elementary school teachers. To set up five IITs and five IIMs the allocation is Rs. 500 crore. I want the Finance Minister to set up an IIM in Tamil Nadu also.

Our Hon'ble Chief Minister 'Amma' is implementing various welfare schemes like issue of free lap-top. Computers to all students, issue of free school note books to all students, free cycles to all students, rain harvesting schemes, 'Amma' eatery to provide cheap and best meals to all, 'Amma' pharmacy etc.

In my coimbatore constituency lot of schemes/projects to be done for the welfare of the people of my constituency.

The existing National Highways No. 67 from Chinthamanipudur to Kakanadu via Coimbatore, Mettupalayam Coonoor, Ooty and Gudalur –approx. 171 kms needs to be converted into four lanes to cope up with heavy traffic congestion on these roads.

The existing National Highway No. 209 from Madathukulam to Thimbam via Pollachi, Coimbatore and Sathyamangalam approximately 190 kms needs to be converted into Four lanes to cope up with heavy traffic congestion on these roads.

Coimbatore may be brought under a centrally sponspored Solar public lighting program to use less expensive Night Lighting which will incidentally become the first such effort in the country.

Setting up of high profile and top technical institutions like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Management in Coimbatore.

Setting up of multispecialty hospital in Coimbatore as it is the only city which can provide health care facility to the entire District.

As Coimbatore is called as the Manchester of South India, a textile park may be set up in Palladam which is nearer to Coimbatore city. A national school for Design and Development may also be set up there.

Supply of coal, iron ore and other raw materials are to be supplied at no tax cost to SME foundry units and the feeder units of pump industry.

Nationalized bank branches may be opened in all villages in my constituency to enable the NREGP beneficiary to avail this facility.

Jurisdiction of Debt Recovery Tribunal, Coimbatore to be retrieved to original status to include Erode, Salem, Namakkal and Karur districts to facilitate the borrowers to reach the adjudication institution easily.

For the benefit of farmers and agriculturists, a Agri Storage Complex with cold storage facility to be set up in Coimbatore. A cargo complex must have large cold storages equipped with freezer.

The Coimbatore Civil Airport to be developed and modernized to operate more flights from there.

I request the Hon'ble Finance Minister to accede the above requests and release the necessary funds during this financial year itself.

With these words, I support the General Budget, 2014.

ओडॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा) : मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व में माननीय वित मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट निश्चित रूप से देश के हित में गरीबों, किसानों, व्यापारियों एवं सर्वजन हिताय वाला बजट है। इस बजट में एक अच्छे, मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना परिलक्षित हो रही है। पिछले 10 वर्ष तक जो यूपीए सरकार ने देश को आर्थिक खोखला बना दिया। इस कमी को दूर करने के लिए यह महतवपूर्ण बजट है। मैं इस बजट का स्वागत करते हुए अपने क्षेत्र लोक सभा क्षेत्र आगरा एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जाना जाता है। आगरा में प्रतिवर्ष 8 लाख विदेशी 80 हजार स्वदेशी पर्यटक आते हैं। आगरा में लंबे समय से मांग है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने यह हमारी प्रार्थना है। आगरा में आर. वी. एस. डिग्री कालेज जो कृषि विद्यालय है इसके पास 100 हेक्टेयर से अधिक जमीन रोड पर स्थित है। हम मांग करते हैं कि आगरा के आर.वी.एस कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए तथा पर्यटकों की दृष्टि से आगरा में यमुना नदी जो कि एक तरफ किला और दूसरी ओर ताजमहल उस कोरी डोर का विकास किया जाए। आगरा में एस.एन. मेडीकल कालेज देश के प्रमुख पुराने 4-5 कालेजों में एक है जिसके पास लगभग 100 हेक्टेयर से अधिक जमीन शहर के मध्य में वहाँ एम्स बनाया जाए।

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): I thank Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu Puratchitthalaivi Amma for making me a Member of Parliament representing Thanjavur constituency. on behalf of AIADMK and Thanjavur constituency, I want to participate on the discussion of General Budget of

2014-15. This is my mainden speech. My Thanjavur constituency is called the granary of Tamilnadu. Many people in my constituency are dependent on Agriculture. I thank you, on behalf of Puratchitthalaivi Amma, for allocating adequate funds for agriculture, cattle breeding and rural development.

A couplet of Thirukkural by famous poet Thiruvalluvar says, "World revolves behind the plough; and hence agriculture remains the primary occupation".

The leader of AIADMK Puratchitthalaivar MGR said, "God, the employer found a wonder employee called the farmer". Under the Prime Minister's Agricultural Irrigation Programme, an amount of Rs. 1000 crore was allotted for the welfare of farmers and development of irrigation facilities. I thank the Government on behalf of Puratchitthalaivi Amma. I welcome the Schemes of the Government like Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission for infrastructure development in rual and urban areas, Deendayal Upadhyaya Rural Electrification Scheme for providing electricity to rural areas and Prime Minister Rural Roads Scheme for providing road connectivity in villages. I request that adequate funds should be allocated to Tamil Nadu in order to provide benefits of these schemes to the people of Tamil Nadu. Government under Aajeevika Scheme (National Rural Livelihoods Mission) has decided to provide loans on less interest to Women Self-help Groups in 100 districts of the country. The districts of Tamil Nadu, particularly my constituency Thanjavur, should be included in the list of 100 districts which would be benefited by this scheme. Swachh Bharat Mission proposes to provide individual household latrine units throughout the country 2019. I urge for necessary action in this regard for the benefit of Tamil Nadu.

Union Government has decided to set up Agricultural Research Institutes with an aid of Rs. 100 crore. In future such an institute should also be set up in Tamil Nadu. Union Government has allotted Rs. 50 crore for inland fishing and cattle breeding. Hon. Puratchitthalaivi Amma is providing milking cows, goats to people below poverty line in order to secure their livelihood. Union Government should allocate adequate and necessary funds for implementation of such welfare schemes and for improving agricultural and cattle breeding in Tamil Nadu.

A famous of Sangam Literature highlights the importance of agriculture. While felicitating a king, a lady poet called Avvaiyar said as under:

"If the boundary level rises; the water level rises.

If the water level goes up; there is a good harvest of paddy.

If there is good harvest of paddy; the family becomes self- sufficient.

If the family becomes self -sufficient ; the ruler becomes happy"

Under the able leadership of Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchitthalaivi Amma and Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi the good fortune has favoured the country. There is an indication to this in the budget which attaches importance to agriculture. This budget not only attaches importance to agriculture but also ensures for rural development.

Only in the development of agriculture the livelihood of citizens could be improved. If the livelihood of citizens is improved, the State Government will prosper. If the Government prospers it brings prosperity and strength to the nation.

Under the "Vision Tamil Nadu 2023" scheme inaugurated by Hon'ble Chief Minister Puratchitthalaivi Amma the Tamil Nadu, the State Government needs an amount of Rs. 1 Lakh crore to tackle the financial challenges in the State. Union Government should start a scheme for ensuring urban development providing housing facilities and developing infrastructure. On the basis of urban population Union Government should also allocate funds to the State Government. This finance sharing scheme having 70 percent share by Union Government 15 percent each by State Government and local bodies should be implemented.

An amount of Rs. 7000 crore has been allocated to create 100 Smart Cities. Some cities of Tamil Nadu particularly Thanjavur should be included in the list of smart cities.

Thanjavur has a history and tradition of thousands of years. There is a thousand year old Brahadeeswarar temple in Thanjavur. Iravadewarar temple in Darasuram and Gangaikonda Chozhapuram temples in Jayakondam have been declared as World Heritage Site by UNESCO under the category of Chola temples. Thanjavur should be declared as a heritage tourist centre by the Union Government. Thiruvaiyaru Music Festival, Bharathanatyam, Tanjore arts, Sculpture and several famous temples adore the glory of Thanjavur.

In my Thanjavur Constituency and nearby places there are temples for nine planets. Therefore, it is a pilgrim centre which attracts thousands of pilgrims from throughout the country. Union Government should allocate adequate funds for infrastructure development of Thanjavur besides announcing it as a heritage tourist centre and pilgrims centre. Thus urban development works like providing air travel facilities, sufficient rail connectivity, hostels, etc should be undertaken to Thanjavur for improving tourism. I, therefore, urge that Union Government should provide adequate funds for improving infrastructure in Thanjavur. Moreover thanjavur should be declared an World heritage site.

I, therefore, urge to announce Thanjavur as World Heritage Site and provide necessary financial allocation for developmental work in the constituency.

I hail the budget. I once again thank Puratchiththaliavi Amma for allowing me to speak me on this discussion on General Budget of 2014-15.

*m25

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बजट की इस विस्तृत चर्चा में भाग लिया है। चर्चा लगभग 15 घंटे चली है। जो थोड़ा समय मैं लूंगा, वह अतिरिक्त होगा। कुल 77 सदस्यों ने भाषण देकर इस चर्चा में भाग लिया है और इनके अतिरिक्त 87 वे सदस्य हैं, जिन्होंने अपने लिखित भाषण टेबल पर रखे हैं।

मुझे बहुत कम चर्चाएं याद हैं बजट पर, जिनमें इतने अधिक सदस्यों ने भाषण के माध्यम से या लिखित माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किया हो। इससे केवल एक बात स्पष्ट होती है कि अब राजनीति के केन्द्र बिंदु हैं, centre stage of politics. उनमें आर्थिक विषयों का अपने आपमें महत्व हो चुका है। इस सदन के सभी दलों के प्रतिनिधियों को लगता है कि अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है, प्रगति और विकास होता है, तो शायद उसी के माध्यम से इस देश का भी उपकार होगा तथा इस देश में गरीबी को समाप्त करने में हम योगदान दे पाएंगे। माननीय सदस्यों ने इतनी अधिक रुचि ली है कि मुझे कई बार लगा कि अगर एक शुरूआत करनी है तो केवल अपने दल के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर हम परिस्थिति को देखें।

पिछले 23-24 वर्षों में, 1991 के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आई थी। पूरे विश्व को लगता था कि भारत एक प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था। अलग-अलग चरित्र में सरकारें आई, लेकिन हमारी जो नीति थी, उसकी एक दिशा थी कि किस प्रकार से देश की विकास दर बढ़ पाएगी। सबको लगता था कि अगर विकास दर बढ़ती है और देश प्रगति करता है तो कुछ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और सरकार की जेब में जो अतिरिक्त साधन आएंगे, हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से, सारे कमजोर वर्गों की सहायता कर पाएंगे। लेकिन आज जिस परिस्थिति में सरकार में परिवर्तन हुआ, एक प्रकार से पिछले तीन-चार वर्षों में विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में एक निराशा का माहौल पैदा होने लगा था। निराशा का माहौल होते ही हमारी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। There was a serious question on the credibility of our economy. यह प्रश्न चिन्ह ऐसा था कि बाहर के निवेशकों को लगता था कि आपकी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी जो टैक्सेशन पालिसी है, उसकी स्थिरता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई शब्दावलियां जो कभी हमने पहले सुनी नहीं थी- Policy paralysis, tax terrorism. ये सब शब्द ऐसे थे जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में पहली बार प्रयोग हुआ। These idioms were added into the vocabulary of Indian Economic Management for the first time. इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में से हम सबको सीखने को क्या मिला है, वह सबक भी हम लोग सीख लें। ताकि आने से किसी की भी सरकार हो तो इस प्रकार की भूल हम लोग न करें। स्वाभाविक है कि एक बात सीखने को यह मिली है कि किसी भी सरकार में जो प्रधान मंत्री होते हैं अंतिम शब्द उनका होना चाहिए। इसलिए एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रशासन में मंत्रि-परिषद् के माध्यम से उनको नीति बनानी चाहिए। No Finance Minister can ever implement any major decision without the support of his Prime Minister. केवल हम लोकप्रियता के पीछे चले जाएं और उस आड़ में जो एक स्थिर नीति हो सकती है जो अर्थव्यवस्था में अनुशासन ला सकती है, उसे नजर-अंदाज कर दें तो शायद उससे अर्थव्यवस्था में लाभ नहीं होता। हमने कई बार देखा है और राज्य सरकारों में हाल के चुनावों में भी देखा है, इससे पहले राज्य असेम्बली के चुनावों में भी देखा कि लोकप्रियता का निर्णय ले लिया और लगता था इससे बहुत वोट मिलेंगे, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो केवल उससे बहुत असर पड़ा है ऐसा नहीं हुआ।

भ्रष्टाचार और उसके जो परिणाम आते हैं उससे किसी भी अर्थव्यवस्था पर उलटा असर पड़ सकता है। हमारे देश में चाहे स्पैक्ट्रम का विषय था, कोयला आवंटन का विषय था, पूरी दुनिया और भारत के निवेशकों में भी मन के अंदर कई प्रश्न-चिन्ह खड़े हुए। टैक्सेशन की एक स्थिर नीति नहीं थी। We did not have a stable tax policy. A defining moment against us, both to the domestic investors and international investors, was the idea of a retrospective tax. Any economy, which can enact a retrospective tax and say this applies 40 years earlier, destabilises businesses, and, therefore, the world was not willing to accept it.

One of the other lessons which we all seem to have learnt is that if we want to grow as a nation, on major issues, at least amongst the major political parties, to the extent possible, we have to have some consensus on policy issues. Some issues may not be policy issues but there is a large space where in the larger national interest, it is possible, and, therefore, I would urge everybody in this House that when we plan our economic policy, at times there may be little scope for differences; and there may be many issues where there is a huge scope for differences.

Madam, we have reached a situation today where the last two years particularly have been challenging. Our growth rates for a considerable period of time were in the vicinity of eight per cent or nine per cent. This was the result of a lot of polices from 1991 till 2004 which successive Governments have followed. We have in the last two years suddenly seen a dip in our growth rates. Two years ago, we grew only by 4.5 per cent. Last year our GDP has grown by 4.7 per cent. This has had an adverse impact on our economy. If the economy does not grow, tax buoyancy does not pick up, the tax GDP ratio does not grow. Last year, for example, the tax GDP ratio was only 10.1 per cent, one of the lowest in current memory.

Jobs do not grow. So, even if you have a marginal growth, it is without jobs. Our saving rate dips. So, in one year from 33 per cent savings, we have come down to 30 per cent savings, and these are savings which flow back into the system and they are further used for investment purposes. Our manufacturing growth was a cause of concern. Services sector in different countries grows and in a country like India it grows on the strength of individual initiatives.

Agriculture sector has seen a huge amount of underemployment. But, manufacturing is the area where jobs are. Successive Governments have said that we want 25 per cent of our GDP to come from manufacturing. It has come down to almost 15 to 16 per cent. If manufacturing goes down, jobs do not get created; taxes do not get collected. Tax collection falls because Excise Duties fall, Customs Duties fall and jobs fall. In the last two years we have seen either a flat growth in manufacturing or a negative growth. So, the investment levels are low. Inflation has been very high.

In addition to this – because we have been a welfare State in at least some minimal sense – we have reached a situation where our subsidy is quite high. We have added to it. At times there are sections of Indian society – because if 30 per cent odd people live below poverty line – which need to be subsidised. But, then, subsidy at times has also become an unquantified amount which is given to an unidentifiable section of people. So, that section of people, which is not entitled to subsidy, also gets subsidised; whether it is educational subsidies or subsidies in the oil sector. It is this situation which we need to correct. This is not a problem of either the UPA till 26th of May and for the NDA after 26th of May. It is a problem, which is common to the entire country and whoever is in Government will have to really seriously address this problem.

It is too early to say as to whether this trend can be reversed. There are first signs – I would say with a great element of caution that it is only very preliminary signs, which have appeared – and it looks like if we follow a certain amount of discipline, we can try and reverse this trend. For instance, from a negative manufacturing growth in April-May when the index of industrial production was four per cent, it becomes a little positive as in June it is 4.2 per cent.

My predecessor in February had given a number of excise concessions lasting to 30th June for the manufacturing sector. I have extended all those concessions at a considerable tax sacrifice by the Government. We have started seeing the result in June in auto sector. Auto sector is one, which is the major sector in Indian manufacturing. So, revival of auto sales has taken place. In capital goods, there is some improvement which is visible. In exports on the external sector, some improvement is visible. In capital inflows, there is a significant improvement which is visible. But, as I said, it is too early to assume that this is a trend. This is only the first sign.

Can inflation moderate because July to November – part of the season between two crops – is normally a season where prices of agricultural commodities, vegetables, etc., go up? So, one has to be very careful and keep them under control. For the month of June, the Wholesale Price Index increase is 5.43 per cent and the Consumer Price Index is 7.31 per cent. This is the lowest in the last 30 months. I cannot really say – as we took over only on the 27th – that I claim credit for it because this is a continuation of several .

As a result of this, if we are to continue and make this first observation into a pattern or a trend, then I think, there is a series of steps which we have to take. The Budget included only sone of those steps. It was directional. वह केवल एक दिशा दिखलाता है। अधिकतर ऐसे कदम होंगे तो बजट ढांचे से बाहर होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ बजट में घोषित हो। सरकार का लेखा-जोखा बजट में होता है लेकिन बजट के बाहर जो आपको कदम उठाने हैं, जब भी सरकार को लगता है कि सुधार लाने की आवश्यकता है, सुधार लाते हैं पहले भी लाते रहे हैं। एक रिवाज बना है राजनैतिक तर्क देने का कि व्यापार और व्यवासायी के पक्ष में कौन है और गरीब के पक्ष में कौन है? जैसे ये दोनों चीजें आपस में अन्तर्विरोधी हों। अगर हम देखें कि इस देश का आर्थिक ढांचा बन रहा है, स्वाभाविक है कि देश के आर्थिक ढांचे में हमें निवेश चाहिए, पूंजी चाहिए। देश के भीतर से पूंजी आएगी, देश के बाहर से भी आ सकती है। मैं अलग से एफडीआई की बात करूंगा। किस क्षेत्र में एफडीआई आए या किसमें न आए, यह निर्णय देश करे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमारे साधनों में यह जुड़ सकती है and it can be an additionality of resource. If you do not have resource, you do not have economic activity. Then, you are destined to do. हमें निवेश चाहिए। उस निवेश के माध्यम से जब इकोनामिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसमें से रोजगार पैदा होता है। अगर वह थोड़ा सा मुनाफा कमाती है तो उसमें से राजस्व पैदा होता है। उस राजस्व से सरकार की जेब में जाता है, सरकार इफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं बनाती है। आर्थिक गतिविधि का लाभ यह होता है कि जो लोग उस ढांचे में शामिल हो जाते हैं, स्वाभाविक है कि उन लोगों के गरीबी से उठने का अवसर मिल जाता है। इस देश का अनुभव यह है कि केवल विकास होने से गरीब क्या गरीबी में से निकल जाएगा, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हर सरकार अपनी राजनैतिक विचारधारा के अनुकूल उसे हटाने की कोशिश करती है। There will be some pull out, but then you have to pump sufficient resources to make sure that they reach the poor. जो सरकार किसी आर्थिक गतिविधि से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकती तो वह गरीबी का उन्मूलन कैसे करेगी? वह तो गरीबी को पाटने का प्रयास करेगी। It will only distribute poverty. It has to earn an economic resource from economic activity and that resource may help to pull up some people and then additionally use it for poverty alleviation schemes. जब इफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो लोग देखकर और निवेश करते हैं। मुझे लगता है कि जब हम इस दृष्टि से देखें, जब बजट पर चर्चा आरंभ हुई तो मुझे विचित्र लगा जब सिंधिया जी ने यह कहा कि लगता है कि यह हमारी पार्टी का बजट है। जब उन्होंने यह कहा तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मुझे लगा कि अब वह बजट की प्रशंसा करेंगे क्योंकि यह उनका अपना बजट है। जब वह मेरी तरफ देखते थे तो कहते थे कि हमारा बजट है और जब अपनी साइड में पहली पंक्ति की तरफ देखते थे तो आलोचना करने लग जाते थे। Let us seriously consider what the difference in approach is. The difference in the approach is that consistently across the board, this is a Budget where we have not increased taxes. One of the reasons why we have not increased taxes is because this is Prime Minister's own philosophy, and I fully support the Prime Minister on this, that if you have a reasonable rate of taxation on products, it is bound to encourage economic activity.

If you put higher taxes on products, you make them costlier and then the principle is that the consumers will buy what they get the cheapest. They will not buy your products; and they will buy products from outside. इस देश के जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हैं, उन्हें कैसे कॉम्पिटेटिव बनाना है। क्या उस पर ज्यादा टैक्स लगाने से कॉम्पिटेटिव बनेगा या उसको प्रोत्साहन देने से बनेगा? So, lower taxes will increase economic activity. मैंने पहले जो प्रश्न रखा, किसी ने कहा कि हम प्रो-बिज़नस हैं। हाँ हम हैं। इस देश के निजी क्षेत्र में बिज़नस एक्टिविटी बढ़ेगी, उसी में रोज़गार बढ़ेगा, उसी से राजस्व आएगा और उसी से गरीबी का उन्मूलन होगा Madam, there is no contradiction in being pro-business and being pro-poor. In fact, if you stop business activity, then you would not have enough resources to service the poor as far as this country is concerned. So, I see no contradiction in this. इस बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास किया है। किसी भी सोशल सैक्टर स्कीम में से एक रूपया भी कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया ही है। मुझे नहीं याद आता है कि पिछला कौन सा बजट था, जिसने निजी करदाताओं को इतनी रिलीफ देने की कोशिश की हो। When you say that it is your Budget, the retrospective tax mess was created by you. We have tried to substantially resolve the problem. The whole regime of tax terrorism where civility had to be added to it, the problem was created by you. How can the two be similar? So, as far as taxation is concerned, we have said that there will be no retrospective tax as far as the future is concerned. We have given a cushion that we would not tax people retrospectively creating fresh liabilities. We are trying to create an environment where GST be enabled in this country. We have taken a radical step by saying that the facility of advance ruling will be available when Indians invest in business in India. The non-residents were entitled to it. आप व्यवसाय शुरू करने से पहले पूछ लीजिए, एक थ्रेशहोल्ड से पहले आपको बता देंगे कि आप पर कितना टैक्स लगता है, so that subsequently your businesses do not become unmanageable. 4 लाख करोड़ रूपया टैक्स विवादों में फंसा हुआ है। उसको रिसाल्व किया जाए, उसके लिए सैटलमेंट कमीशन बने। उद्योग का, टैक्स पेयर्स का सरकार का और सीबीडीटी का इंट्रैक्शन हो, बातचीत हो और उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टैट्युटरी शेप दे दी जाए। इस देश में हज़ारों हज़ार करोड़ रूपये, विशेष रूप से उन लोगों के जो बाहर से निवेश कर रहे हैं, ट्रांस्फर प्राइसिंग के झगड़ों में पड़ा हुआ है। सिंधिया जी तो बैंकर रहे हैं। यह विषय उनको मालूम है। उनका अध्ययन इस पर शायद मुझसे ज्यादा होगा। जिन लोगों ने देश में निवेश किया, उनके हज़ारों-करोड़ों रूपये झगड़े में पड़े हुए हैं। उनमें से कई लोग हमारे पास आते हैं और वे कहते हैं कि हम अपना उद्योग बंद कर के वापस जा रहे हैं। उसको गाइडलांइस देना, उसका हल करने की कोशिश करना, केवल 6 सप्ताह के समय में इस काम को करना सरल नहीं था। ये काम तो पहले भी हो सकते थे। इस पर तो कोई वैचारिक झगड़ा नहीं था।

सुदीप दा ने विषय उठाया कि डिफेंस में एफडीआई क्यों आया? आज जो स्थिति है, उसमें 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इस पर दो प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं। पहली टिप्पणी है कि आपने कहा कि डिफेंस में एफडीआई क्यों आया। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हमारा 70 प्रतिशत डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों से आ रहा है। फॉरेन कंपनीज से आता है, निजी कंपनीज से आता है, सरकारी कम्पनियों से आता है। कितने लम्बे युद्ध के लिए डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए और हमारे पास कितना है, यह प्रश्न है। There are those who oppose the idea of FDI in Defence at 49 per cent. I cannot understand the contradiction: "You can buy 100 per cent from foreign companies and foreign Governments, but I will oppose if you set up an Indian company with 51 per cent and start manufacturing in India." Today the situation is that we are buying from foreign companies and foreign Governments. Our 'defence' is in their hands. They can stop supplies. We have to build capacities. DRDO is building this capacity. When Vajpayee Ji made it 26 per cent, a few business houses, large ones, Tatas, Larsen & Toubro, Bharat Forge, Mahindra's, have started some defence establishments. The offset policy which the UPA had been following also has helped it. So, I was faced with two choices.

The other criticism is, Mahtab Ji argued that point, "make it 51 per cent, if you want technologies to come in." If I make it 51 per cent and give the majority control to outsiders, then I am only shifting the location of his plant from a foreign soil to an Indian soil. It remains under his control. If I allow 26 to continue, then I have no option but to buy from foreign soil. So, I have to build up domestic, indigenous capacities in matters of 'defence'. I am aware of the fact that the UPA Government also, at some stage, was contemplating 49 per cent. But we have said, "FIPB route and Indian control". We think, under the circumstances, this perhaps may be the best policy. It is much better than the present *status quo* where 70 per cent of our Defence equipment comes from outside and a large foreign exchange outgo takes place.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is DRDO doing?

SHRI ARUN JAITLEY: DRDO is doing quite a lot, which I have explained in the morning also. However, DRDO may not be able to have all supplies, as far as the Indian Armed Forces are concerned. We are one of the largest Armies in the world. Our Defence requirement needs much more. Therefore, we have to build up domestic capacities. I would, therefore, urge hon. Members that under the circumstances, the 49 per cent approach that we have followed is perhaps in larger national interest.

There are public sector insurance companies – LIC has done a great job; other public sector companies have done a very good job; and there are also private sector insurance companies. However, the insurance sector is investment starved. Health insurance in this country, आज किसी को निजी अस्पताल में जाकर इलाज करवाना पड़ जाये तो फिर पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितनी कम है इस देश में। दुनिया के जिस देश में हेल्थ केयर डेवलप हुआ है बड़े पैमाने पर, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। हमारे यहां इंश्योरेंस में साधन नही हैं। वही सिद्धान्त हमने वहां लगाया कि इंडियन मेजोरिटी, इंडियन कंट्रोल 49 परसेंट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का बढ़ाना चाहते हैं, ये 100 स्मार्ट शहर कोई एक वर्ष में नहीं बनेंगे। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि आप तो 50 वर्ष से ज्यादा सरकार में रहे, जब नयी योजना बनती है और सालों-साल के लिए बनती है और उस साल

में जब एक तिहाई साल बीत चुका है, एक तिहाई और लगेगा अभी योजना बनाने में, मान लीजिए हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में एम्स बने। इस वर्ष हम 100 करोड़ भी देंगे तो 100 करोड़ में तो एम्स नहीं बनेगा। लेकिन इस बार तो जमीन आयेगी, उसकी पूरी प्लानिंग होगी, नक्शे पास होंगे और जो 100 करोड़ देंगे, उसमें से शायद 10-20 करोड़ से ज्यादा इस साल खर्च नहीं होगा। फिर अगले साल दोबारा देंगे। यह पूरे एम्स के लिए नहीं होता। यूपीए के कार्यकाल में तो योजना जब शुरू करते थे, 100 करोड़ तो छोड़िए, एक करोड़ पर भी बजट में योजना शुरू हुई है। आपने योजना शुरू की और जब उसके लिए जितने साधनों की आवश्यकता होती है, उतने मिलते हैं। पूरी योजना के लिए 100 नहीं होता। 100 स्मार्ट सिटी बनने में तो इस देश में दशक लगेंगे लेकिन क्या देश के सिर्फ 35 परसेंट लोग शहरों में रहें और बाकी देहातों में रहें, उनको सुविधा न मिले? Urbanisation and sub-urbanisation is the current trend. World over, it is the trend. बड़े शहरों के आस-पास छोटे शहर बस रहे हैं, वे स्मार्ट सिटीज़ हैं। आज नया रायपुर, गांधीनगर, नौएडा, गाज़ियाबाद - ये सब स्मार्ट सिटीज़ हैं। इस प्रकार के शहर अगर बसने हैं तो 7000 करोड़ रुपये में नहीं बसेंगे, लेकिन जो आरंभिक साधन उसके लिए दिये जा रहे हैं, जब उसकी योजना बनेगी, और अभी तो पाँच-सात भी शुरू हो जाएँ, शहर बनने और बसने में तो फिर दशक लगते हैं। उस दिशा में जाएँगे, निजी क्षेत्र आएगा, इस सारे क्षेत्र के लिए हमने इसमें सुविधाएँ बनाई हैं। बैंक कैपिटलाइज़ेशन की बात है। आज हिन्दुस्तान का बैंकिंग सिस्टम केवल 58 फीसदी लोगों तक पहुँचा है। अगर 90 और 100 फीसदी बनाना है तो उसको साधन चाहिए ताकि लोग ऋण भी ले पाएँ। बैंक्स का रीकैपिटलाइज़ेशन करना, जिसके लिए to fill up the Basel-III norms and by the year 2018, we will maintain the public character of the Public Sector Banks. The Government will always have a majority. Some surplus shareholding is disposed of, not to a business house but in the market. Today, people of India own these banks through the Government. The Government will continue to have majority stake. But if some surplus goes to small retail investors, you can get Rs. 2,80,000 crore by the year 2018 where banking inclusion of 58 per cent can go up to 80 or 90 per cent. Now, it is a resource available with us.

हमने टूरिज़्म के क्षेत्र में कहा कि कुछ देशों को छोड़कर जहाँ सुरक्षा कारण हो सकते हैं, इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा या वीज़ा ऑन एराइवल देंगे। ये जो कलैक्टिव योजनाएँ हैं, पूलिंग रिसोर्सेज़ से रीयल एस्टेट बने। चाहे शहर बसें, चाहे छोटे शहरों में जाएँ, जो रीयल एस्टेट इनवैस्टमैंट फंड्ज़ और इनफ्रास्ट्रक्चर इनवैस्टमैंट फंड्ज़ हैं, उनको टैक्स की छूट चाहिए थी पास-थ्रू के लिए। जब कंपनी ट्रस्ट बनाती है तो उस पर टैक्स न लगे और इसलिए वह रिसोर्स आ जाए। पूरी दुनिया के कई देशों में यह सफल मॉडल रहा है। उसका प्रयोग करना ताकि इनफ्रास्ट्रक्चर में पैसा और साधन इसके माध्यम से आने लग पड़ें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में पावर सैक्टर को इंसैन्टिवाइज़ किया जाए। पावर सैक्टर बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह देश बिना पावर सैक्टर के प्रगति नहीं कर सकता। वह छूट हमने टैक्स की दी कि जो लोग बिजली बनाने में निवेश करेंगे, उनको टैक्स इंसैन्टिव मिलेगा। इनवैस्टमैंट अलाउंस उन लोगों को मिलता था जो सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा लगाते थे। सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा लगाने वालों की संख्या कम है। हमने उसको 25 करोड़ रुपये कर दिया। जो एम.एस.एम.ई. सैक्टर है, उसमें इससे एकदम उत्साह आया है। कई एक्साइज़ और कस्टम्स रीबेट्स हमने कई क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर्स को दिये हैं, जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सकता है।

टैक्सटाइल क्लस्टर्स और इंडस्ट्रियल कॉरीडोर्स यूपीए के ज़माने में भी शुरू हुआ। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसको सफल बनाना है, उसी से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाना, नई हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाना, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग इस देश की हो। सॉइल हैल्थ, सस्ता ब्याज, भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख संयुक्त खेती की योजनाएँ जिनको सरकार की तरफ से साधन मिले। बैंक क्रैडिट एग्रीकल्चर सैक्टर में इस वर्ष 8 लाख करोड़ तक जाए और जहाँ किसी वस्तु की कीमतें कम हों तो प्राइस स्टैबिलाइज़ेशन फंड उसके लिए है। ग्रामीण इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25000 करोड़ का फंड इकट्ठा हो। पूरे इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्मार्ट सिटीज़, बिजली, शिपिंग, एयरपोर्ट्स, हाईवेज़, रूरल रोड्ज़ - एक एक योजना के संबंध में हमने इसमें टिप्पणी की है।

There is no contradiction, as I said. You have to get the economy moving; you have to get the economy to provide you larger resources. Those resources have to be used for the poor. अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यापार को, व्यवसाय को कुछ प्रोत्साहन देते हैं तो उसी से गरीब आदमी का कल्याण करने के लिए साधन आपकी जेब में आएंगे। जितनी योजनाएं थीं, वन बंधु, एससी-एसटी वर्ग से आने वाले व्यवसायियों के लिए स्टार्टअप वेंचर कैपिटल, वरिष्ठ नागरिक, विजुअली डिसएबल्ड, फ़िज़ीकली चैलेन्ज्ड, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, जो बिलकुल असहाय है, लाइवलीहुड मिशन, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वॉटर, इस सब क्षेत्रों में जा कर हम लोगों ने हर एक के लिए विस्तृत योजना को वर्णन इस बजट में किया है। मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि एक-एक राज्य के सांसद आ रहे हैं कि आप जो राज्यों में आईआईटीज़, आईआईएम्स आप दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स बना रहे हैं, मेरे राज्य में यह रह गया है, इसको ज़रूर कीजिए। राज्यों में और उनके सांसदों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है। यह अच्छी प्रतिस्पर्द्धा है कि मेरे राज्य में और देने का प्रयास कीजिए। कुछ को हम लोगों ने दिया है और यह कोशिश की है कि कोई राज्य इसमें से बाहर न रहे और जैसे ही सरकार के साधन बढ़ेंगे, मैंने एक-एक माननीय सांसद की बात नोट की है, जितने लोग बोले हैं या जिन्होंने लिखित में अपना भाषण दिया है, जिनके राज्य इस में रह गए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ इस साल जुड़ जाएंगे, कुछ आने वाले सालों में जुड़ेंगे।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में कानून में और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. साहब ने जो भी अपने वक्तव्य में दोनों राज्यों से वायदे किए थे, उसको सौ फ़ीसदी हम लोग निभाएंगे।

कई ऐसे विषय थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि दिया भी जाता था तो योजनाएं सफल नहीं होती थीं। कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित भाई हैं, अगर उनको पुनः स्थापित करना है या कोई उस राज्य से बाहर आ गया है, उसको वापस भेजना है, तो जो साधन हमने दिए हैं, उसमें यदि आवश्यकता होगी और अधिक की होगी तो हम उसको देने का प्रयास करेंगे।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य एक बार इस बात को जान लें कि जो इनकम टैक्स की लिमिट थी, उसे दो लाख से ढाई लाख किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए तीन लाख रुपये किया गया है। There are not many occasions where the limit has been raised by Rs.50,000 even. My friend Dr. Shashi Tharoor is not here. He asked: "Why should it not be Rs.5 lakh?" I wish, his Party had done even half of it. But then this is the beginning. One of my only regrets is that we do not have enough money in our pocket to make it to that figure. But it is not this alone. When I said that savings have come down from 33 per cent to 30 per cent, the 80C exemption being raised from Rs.1,00,000 to Rs.1,50,000, it is to encourage small tax payers and all tax payers to save more. When they deposit it in their savings, that money goes in for national development and infrastructure building. It goes into banks; it goes into provident fund; and it goes into several other securities. There also I have raised it by Rs.50,000.

किसी ने कहा कि पांच हजार रूपए की छूट मिल गयी, तो जो पचास हजार रूपए का प्रयोग छोटी सेविंग्स में करेगा, उसको अलग छूट मिलेगी, दो से ढाई लाख और वरिष्ठ लोगों को ढाई से तीन लाख रूपए तक अलग छूट मिलेगी। हम लोगों प्रोत्साहित करना चाहते हैं और रियल स्टेट सैक्टर को भी, वह ग्रोथ इंजन है। आप मकान खरीदिए या फ्लैट खरीदिए, आपको डेढ़ के स्थान पर दो लाख रूपए की छूट मिलेगी।

We want to incentivise people to buy their own houses. During Vajpayeeji's government a situation had come where paying rent was costlier and EMI was cheaper. Interest rates have gone up. Hopefully if inflation moderates, they may come down. And we want to go back to that situation where buying a house is cheaper than taking it on rent. That adds to national growth because it adds to real estate sector.

आपने बढ़ती हुयी कीमतों का जिक्र किया, वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसका संकेत नहीं देता है, जो आप कह रहे हैं। We said June is the lowest in 30 months, and we are in power only for seven weeks. July to November is a period when prices of vegetables and agricultural commodities shoot up because it is between two seasons. In the last two years, onion went up to Rs.70, Rs.80, or even Rs.100 a kg. We took strict action the moment it crossed Rs.20, and stabilised it at Rs.25. Hopefully as the new crop will come, the price will come down.

बड़ी आलोचना की गयी कि आते ही रेल के भाड़े बढ़ा दिए। Scindiaji, if you want to know the difference between your budgets and ours, your approach and ours, the rail freight and passenger fare increase is a case in point. On 6th of February, it is your Railway Ministry which recommended the increase. Khargeji is here. On the 10th of February, along with Railway Board he met the then Prime Minister. The noting on the file says that it is necessary, it should be done, otherwise, there would be a huge loss and Railways cannot run; but do not do it now, do it in May. You wanted to wait for the

voting. That has what allowed the capacity of a weak-kneed government not to take a tough decision or an unpopular decision. *â€¦(Inaudible)â€¦*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): That is how you did in Maharashtra.

SHRI ARUN JAITLEY: I am glad Khargeji cannot contest the fact that on 10th of February they said increase is necessary but do it in May; we would not do it now; let the economy suffer; let the Railways suffer; my vote should not suffer. ...(*Interruptions*)

The Railway Board officers took a clue from that note and on 16th, when the results were coming in, increased the fares. The fares were increased at 7 p.m. Khargeji called for the file and said, 'Do not increase it today, let the successor decide'. You reversed the order.

So, what your successor did was to consider whether he should go in for populism, not increase fares and let the Railways suffer; or should he implement the wise decision which Khargeji took but did not have the courage to implement. So, he only implemented your decision. And the *volte face* is, you recommended the increase, your Prime Minister approved of the increase, you did not have the courage to implement that increase, and when your successor had the courage and he had broader shoulders, you say, why did you implement the increase that I had recommended, you are anti people. I think we need to get out of this.

The lesson for all of us, Khargeji, is, if we want utilities and infrastructure to survive in this country and if we want to build them up, we have to educate our people. Except those who need subsidies, the others must pay.

15.00 hrs

How have highways been a successful experiment in India? It is because consumers and users have been paying for it. If the users do not pay, there will be no highways. If the users do not pay, there will be no railways. So, let us at least think of sacrificing this populism. We will contest each other in several areas but if the users pay, we will probably have a more modern India with world-class infrastructure.

I had made several proposals – this is my last point – in the Budget itself. A lot of suggestions from outside and from hon. Members with regard to taxation proposals have come to me. I am noting each one of them and I will give my response during the course of the Finance Bill when the debate takes place next week or thereafter but there are two or three areas I wish to inform. One is that in relation to food processing, the Minister also has made a request and some other Members have also requested that in order to make available affordable credit to agro-processing units being designated as food parks, I have decided to announce the setting up of a special fund of Rs. 2,000 crore in NABARD. We will be issuing separate guidelines for this.

Then, there was a little bit of debate with regard to accelerated depreciation in wind energy sector. In the Budget, we have provided for various incentives for wind energy and other renewable sources of energy. I have received more requests for concession. As this is in the nascent stage, respecting the wishes, I will restore the accelerated depreciation benefit for wind energy. Necessary amendments, we will make in the Finance Bill.

There was one more request that I had got. The national effort must go behind the problem of drug addiction in several parts of the country, particularly in the border States next to the Pakistan border; and particularly Punjab has seen this problem in a very challenging way. Therefore, to fight this, we plan to establish drug de-addiction centres in Punjab and I am proposing a sum of Rs. 50 crore as initial contribution for this.

We will get an opportunity to discuss the tax proposals when the Finance Bill is taken up. With these observations, I commend the Budget for approval of this hon. House.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने अच्छी तकरीर की है। वह एक अच्छे वकील भी हैं।...(व्यवधान) आपके लिए तो अच्छा है। ...(व्यवधान) वह अच्छे वकील हैं लेकिन बुरे केस को ले कर बहुत बड़ी वकालत की है।...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : कई बार ऐसा होता है कि बैंड केस एक वकील को छोड़ कर दूसरे के पास आ जाता है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपने वह वकालत ठीक की है लेकिन आप यह नहीं बोले हैं कि जब पावर्टी एलीविएशन के प्रोग्राम्स हैं और वेल फेयर मेजर्स के लिए आपने जो पैसा रखा है, आपने स्पष्टता से कहा है कि उसमें कोई कमी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो फिजकल टारगेट है और आपने जो फाइनैंशियल टारगेट उसके लिए रखे हैं, आज के हिसाब से उस से तालमेल नहीं बैठता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मनरेगा में आप 3 करोड़ लोगों को जॉब देना चाहते हैं, आज के मिनिमम वेजेज के मुताबिक, आपने जो बजट रखा है, उससे मैन डेज कम हो जाते हैं, मैन डेज ज्यादा नहीं होते हैं। शायद, आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। आपने उस के लिए एक हजार करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। जो भी पैसा आपने रखा है, वह टोकन बढ़ाया है।...(व्यवधान) आपका जो फिजकल टारगेट है, कितने लोगों को काम देना है, उस हिसाब से, आज के मिनिमम वेजेज से, अगर देखा जाए तो वह पहले से भी कम है। वह ज्यादा नहीं हो सकता है। यह आप मानते हैं।

दूसरी चीज, अगर टैक्स नहीं बढ़ाते, अगर पिछली सरकार रिवैन्यू कलैक्ट नहीं करती तो कहां से डैवलपमैंट होता, योजना, प्रगति, विकास कहां से होगा। यूपीए सरकार ने ऐसा करके दिखाया, आप कम से कम यह कह सकते थे। अगर हम टैक्स, रिवैन्यू कलैक्ट नहीं करते तो मनरेगा, राइट टू एजुकेशन के प्रोग्राम, फूड सिक्युरिटी जैसे प्रोग्राम कभी नहीं कर सकते थे।...(व्यवधान) हमने रिवैन्यू कलैक्ट करके ही वेल्फेयर मेजर्स किए हैं और इतनी इनकम रहते हुए करके दिखाया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक क्वेरी हो सकती है पूरा भाषण नहीं हो सकता।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, I am asking a clarification. I did not speak on this subject and you know that. अगर हमारे पास रिवैन्यू नहीं होता तो 72 हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते थे। जेटली साहब बहुत ही समझदार और बैलेंसिंग बात करते हैं। लेकिन इसमें मोदी साहब के चक्कर में थोड़ा ऐसा हो रहा है क्योंकि मोदी साहब सब मुक्त चाहते हैं।...(व्यवधान) इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सर्विस के मुताबिक पैसा नहीं दे सकते। आपने कहा कि अगर सर्विस ले रहे हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्विस ले सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं दे सकते। उनके लिए सब्सिडी की जरूरत होती है, उन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है। सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए। हमारी कैपेसिटी है, जब आप सहूलियत चाहते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि रेलवे में बहुत से कनसेशन्स स्टूडैंट्स, डिसएबल्ड, डिफैंस, फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाते हैं। जब आप यह सहूलियत देते हैं तो आपको दूसरी जगह से रिवैन्यू जुटाना पड़ता है। आप कहेंगे कि आप रेल में घूम रहे हैं इसलिए पूरा पैसा दीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जिस विचार से कह रहे हैं, वेल्फेयर मेजर्स को धक्का मत लगाइए। इसमें और बढ़ाइए। गरीबों के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए।

मैनुफैक्चर सैक्टर्स में इन्वैस्टमैंट आने के लिए बहुत से कनसेशन्स, जब प्रणब साहब थे, उस वक्त भी दिए गए थे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, केवल क्लैरीफिकेशन पूछिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी आपने कहा कि मेरे प्रेडीसिसर चिदम्बरम साहब ने जो कनसेशन दिया था, उसे हमने कंटीन्यू किया है। इसका मतलब यही है कि पिछली सरकार भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रैक पर जा रही थी। आप कह रहे हैं कि हम भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

HON. SPEAKER: Shri Mahtab, you may please seek only one clarification.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I will ask only one question. During his speech, the hon. Finance Minister mentioned about the royalty on minerals. He was very categorical in saying that many State Governments have also requested that this royalty should be enhanced, which is due. It was due since 2012. In August 2009, the royalty was enhanced for the last time; it was due in three years' time. Already more than 2Â½ years have passed. He did not categorically state when this royalty enhancement is going to be made.

Alongside that he also mentioned that MMDR Act is going to be amended. We would like to understand what steps the Government is going to take and whether any clear cut date is going to be announced because a number of Chief Ministers have met him. Odisha Chief Minister has also met him. He has also met the Prime Minister. We would like to understand this from the Finance Minister.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the Finance Minister has been good enough to reply to some of the objections or concerns expressed by us. For instance, he has explained the Government's views on increasing the Foreign Direct Investment in Defence and Insurance sector though he feels that it may jeopardize national security. But he has not addressed one concern which we from our side have been raising repeatedly in this House that is the problem of debt stress States.

We have been saying that West Bengal is a State which has a huge outstanding debt burden as a result of which most of its revenues is going in paying back the debt. The West Bengal Government has been asking for a moratorium on interest for at least three years till it could get the economy in order. In spite of our raising the matter again and again the Finance Minister has chosen to remain silent on the matter both in his Budget speech and in his elaborate reply given today.

I would like the Finance Minister to clarify the Union Government's and the Finance Ministry's response to this burning problem of moratorium on interest as demanded by West Bengal, Punjab and Kerala which are debt stress States.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam, I spoke in the debate and would like to seek some clarifications.â€¦ (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have spoken in the debate and that is why I allowed him to seek clarification.

PROF. SUGATA BOSE : I am the Deputy Leader of a Party. I spoke in the debate and would like to seek a small clarification.

HON. SPEAKER: From your Party Prof. Saugata Roy has sought some clarifications. You have already spoken in the debate. I can allow you half-a-minute if you wish to seek a small clarification.

PROF. SUGATA BOSE : Throughout his reply Shri Arun Jaitley, who gave a very fine reply to this debate has stressed that there has been no decline in social sector spending and no cuts in social sector programmes. However, we have pointed out from this side of the House that very nominal, marginal increases have taken place in the education and health Budgets. The drinking water and sanitation Budget is flat. There is no increase. And, therefore, in real term there has been a decrease.

I had said from this side of the House yesterday that the BJP, the ruling Party in its manifesto had said that it would increase spending on education from 3 per cent of GDP to 6 per cent of GDP and I would like to seek a clarification from the Finance Minister that if there is a real decline then what is his time frame for increasing spending not only in education but also health as well as drinking water and sanitation over a period of time to fulfill the promises that the ruling Party made to the country.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, let me start with the response to the last query and I think this will explain the approach not only of this Government but I think that of Centre-State relations this country has to follow. If I have to increase the grant substantially, which I would like to do, I need to have resources. I get resources if India grows at 7, 8 or 9 per cent. I do not get those resources if India grows at four-and-a-half per cent. My tax buoyancy dips. Therefore, much that I would have liked substantially to increase the grants, I have not reduced it anywhere. I am in the middle of a year presenting a Budget for only eight months. My hands are tied with the kind of revenue inflows which are coming on account of the current situation. With the help of the series of steps which we take and because of other overriding factors, we are expecting a modest improvement in the growth rates. That will give me a little bit of tax buoyancy but if we are to get back over the next two to three years to 7-8 per cent growth rate, hopefully we will have sufficient in the kitty to do what you expect us to do. That is the importance of growth and that is the importance which my predecessors also used to emphasise. Therefore, we have to identify what is going to be the roadmap as far as that is concerned.

To Mr. Saugata Roy's question with regard to the debt-stressed States, I just have a small response. I could give a formal response which is that the 14th Finance Commission is seized of this issue. Since it deals with the allocation to the States, we will go by what the 14th Finance Commission says. But at the same time, I would urge some of us because we represent States in this House – some may be historical factors related to a State – that some of the factors where we lacked prudence and we worsened situation in the States, I think we need to introspect on those factors. Let me say collectively as far as the States are concerned, we are at a fiscal deficit of 4.5 per cent last year and targeting 4.1 per cent which I hope to achieve. Collectively the States have a much better figure but it is only a few States which are in a difficulty because of historical reasons. I am sure when the Finance Commission gives its suggestions on this matter, we will be able to look at this.

As regards royalty on minerals, one of the objects behind putting a clear sentence and a commitment to this effect was that there are a large

number of States which are very mineral-rich and Odisha is one of them but the States by themselves are not rich. As a result of which, those who are able to exploit that mineral are really getting the benefit of the wealth as compared to those States who are not doing it. Since 2009, there has been no revision in the royalty. In the course of this year, we certainly intend to look at it and we are very clear about this commitment which I have given as far as the Budget is concerned.

Khargeji made a series of observations. MNREGA is demand based. Of course, we have said that in our Government it will be linked to agriculture and it will be also linked to asset creation. There is some tweaking which will take place but it is demand based. We have not reduced the outlay but we have increased it. You could have had this grievance and that then may have been the only point of grievance if you had seen MNREGA disappear or the amount come down. We have not done that. There will be some changes and the Department of Rural Development will look into those matters. But the fact that the under-privileged in this country need to be helped, we are quite conscious of that fact itself.

Khargeji also raised obliquely an issue and asked how we would raise higher revenues. Do you really raise it merely by increasing the tax rates? You do not and therefore, the approach which we are trying to follow is, expand economic activity and that itself will give you the growth and the buoyancy. It will give you more revenues and those more revenues will also serve as far as the weaker sections are concerned.

Of course, you are right there is a section in India which needs to be subsidised. But then those subsidies will have to be targeted at that section. You and I are not entitled to those subsidies. The trouble today is that you and I get those subsidies as much as those weaker sections do. Therefore, our capacity to subsidise them will be much better if people like us could exclude themselves from these subsidies. So, the subsidies will have to be targeted in order to reach those that need them the most. Therefore, subsidies, as I said, and I repeat the word that I consciously used that it cannot be an un-quantified sum for an unidentifiable section. There must be an identifiable section which should get the benefit of that and probably it will serve the national cause more.

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Excess Grants (General) for 2011-2012 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 13, 21, 24, 31 and 100."

Demands for Excess Grants (General) for 2011-2012 sumitted to the Vote of the Lok Sabha

No. and Name of Demand		Amount of Demand submitted to the Vote of the House	
1	2	3	4
		Revenue(Rs.)	Capital(Rs.)
13	Department of Posts	400,03,82,246	.....
21	Defence Pensions	3568,81,46,182	.....
24	Defence Services – Air Force	567,90,83,321	.....
31	Ministry of External Affairs	.....	7,23,26,294
100	Lakshadweep	1,43,67,211	.....
	Total	**4538,19,78,960**	**7,23,26,294**

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demands for Excess Grants (General) for 2011-2012 are passed.

15.20 hrs